सौजन्य से- उत्तर प्रदेश सरकार

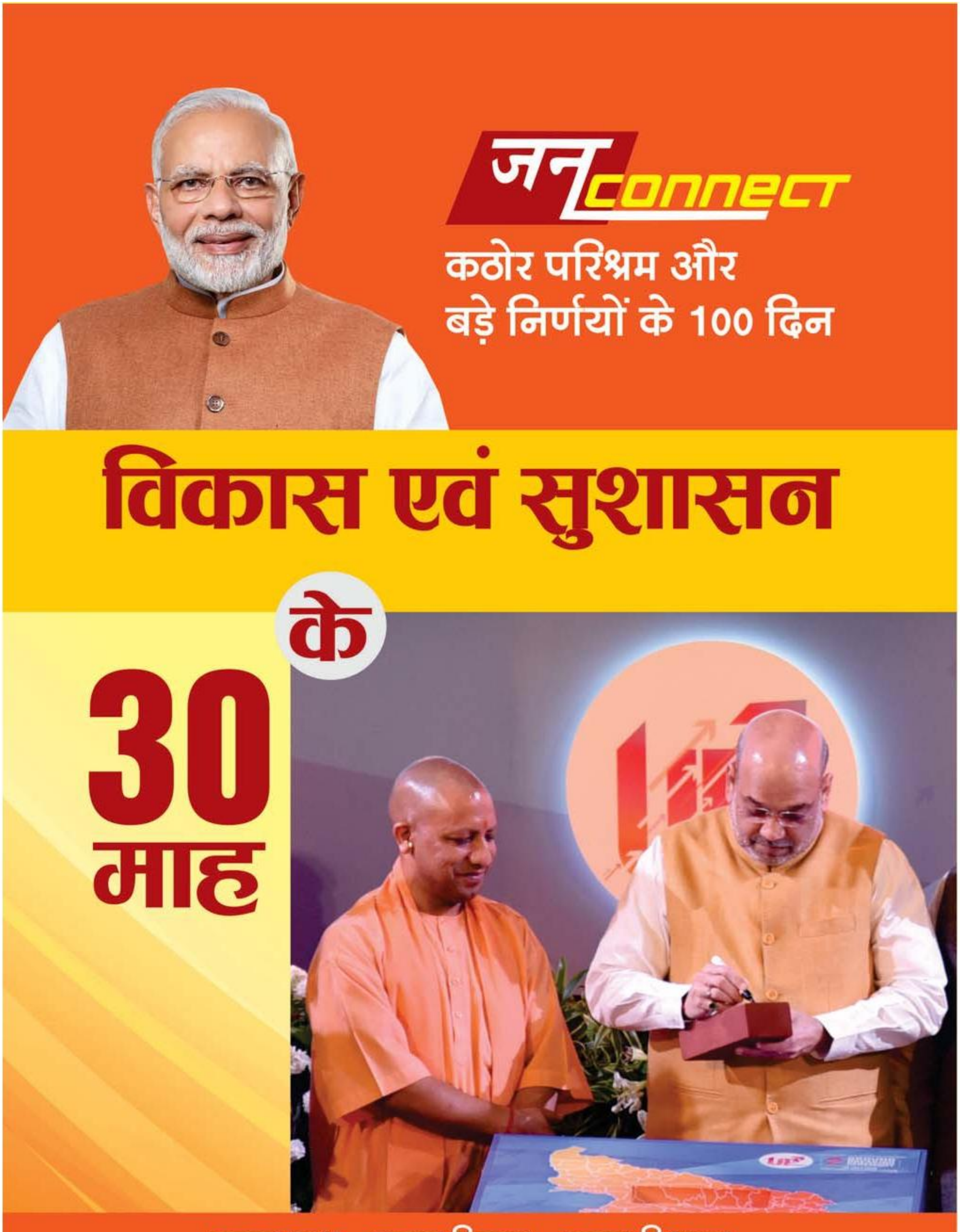

सौजन्य से- उत्तर प्रदेश सरकार

सौजन्य से- उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की यात्रा में 19 सितम्बर, 2019 की तिथि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के पूर्वार्द्ध के ढाई वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार के अगले ढाई वर्षों के कार्यकाल की शुरुआत होगी। जाहिर है कि 19 मार्च, 2017 का संकल्प और उसकी रोशनी में प्राप्त उपलब्धियों पर दृष्टिपात करके ही हम अगले ढाई साल में उत्तर प्रदेश की उभरती सूरत की कल्पना कर सकते हैं। 19 मार्च, 2017 को जब योगी आदित्यनाथ सरकार ने शासन सूत्र हाथ में लिए थे, उस समय उत्तर प्रदेश ऋणग्रस्त किसानों की आत्महत्या, दंगों, सामाजिक तनावों, असुरक्षित महिलाओं, स्कूल जाती बेटियों के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़, अर्थव्यवस्था की बदहाली के दौर से गुजर रहा था। उस समय आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े इस राज्य को उबारने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर डाली थी।

बड़ी चुनौतियों के बीच सरकार ने सबसे पहले तो अपने सभी विभागों की समीक्षा की और 100 दिनों का एजेंडा तय किया। पहली कैबिनेट बैठक में ही 86 लाख से अधिक लघु और सीमांत किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का ऋण मोचन कर उन्हें मजबूत सम्बल दिया। कृषक उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर और विपणन की अच्छी व्यवस्था करके खेती को लाभकारी बनाने का एक बड़ा वायदा भी पूरा किया। दंगों, सामाजिक तनावों, अपहरणों और हत्याओं के लिए बदनाम हो चुके प्रदेश में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए दूसरी बड़ी चुनौती थी। इस दिशा में वर्तमान सरकार ने कानून–व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाते हुए अपराधियों को या तो जेल के अन्दर रहने को मजबूर किया या फिर उन्हें प्रदेश छोड़ने को विवश कर दिया। इससे माहौल बदला और आज प्रदेश में माफियाराज, गुंडाराज, अपहरण उद्योग समाप्त हो गया है।

- **86 लाख से अधिक किसानों का 36 हजार करोड़ रूपये का ऋण मोचन कर उन्हें मजबूत सम्बल दिया।**
- **जी.बी.सी. प्रथम एवं जी.बी.सी द्वितीय तथा अन्य प्रस्तावों के माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रु. की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास।**
- **ओ.डी.ओ.पी. से मिली हर जिले के विशिष्ट उत्पादों को नयी पहचान।**
- **ओ.डी.ओ.पी. के माध्यम से 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला।**

स्त्रियों एवं छात्राओं के प्रति अपराधों में बेहद कमी आई है। उद्यमियों एवं व्यापारियों सहित आम आदमी में कानून–व्यवस्था के प्रति विश्वास फिर से जगा है।

गरीबी और सामाजिक अशांति के कारण पलायन उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या थी और इससे राज्य की छवि देश ही नहीं, दुनिया में भी खराब हो रही थी। यह गर्व की बात है कि अब इन कारणों से राज्य से खासकर बुन्देलखण्ड, कैराना, मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से लोगों का पलायन रुका है और प्रदेश छोड़ चुके लोग वापस लौटने लगे हैं।

उत्तर प्रदेश के आर्थिक नक्शे को मात्र ढाई साल में बदलना भी योगी आदित्यनाथ सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। कहां तो मार्च 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश के लिए कारपोरेट सेक्टर के लोग आ ही नहीं रहे थे और जो थे, वे भी कारोबार समेटने की फिराक में थे, वही लोग माहौल सुधरने के कारण फिर से कारोबार जमाने के लिए उत्तर प्रदेश का रुख करने लगे हैं। फरवरी 2018 से सितम्बर 2019 के बीच मात्र डेढ़ साल में इन्वेस्टर्स समिट, ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी–1 और ग्राउण्ड सेरेमनी–2 का आयोजन हो चुका है तथा राज्य में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की आधारशिला रखी गयी, इससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में बड़े अवस्थापना विकास के नाम पर पिछले 20 वर्षों में मात्र आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे और लखनऊ का आधा–अधूरा काम ही हुआ था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन कामों को न केवल पूरा किया, बल्कि देश के सबसे बड़े पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे पर कार्य शुरू हो गया है और उससे भी बड़े मेरठ–प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस–वे को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जा चुकी है। लखनऊ मेट्रो के अलावा अब कानपुर मेट्रो रेल का काम शुरू हो चुका है और आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी नगरों में मेट्रो का कार्य प्रस्तावित है।

आजादी के 72 वर्षों बाद भी 240928 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में फैले उत्तर प्रदेश में 10 बड़े नगर आपस में हवाई कनेक्टिविटी से वंचित रहे, जिसके कारण यहां पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं हो सका था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नगरों की हवाई कनेक्टिविटी की इस बड़ी चुनौती को भी मात्र ढाई साल में काफी हद तक ठीक किया है। पहले प्रदेश में मात्र 04 एयरपोर्ट थे, जिनसे 25 गन्तव्य स्थल जुड़े थे, परन्तु अब राज्य में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 08 हो गयी है और गन्तव्य स्थलों की संख्या 55 हो गयी है। 11 अन्य एयरपोर्ट के विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। जेवर और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध प्रदेश है, परन्तु बीते 72 वर्षों में नीति–नियंताओं ने यह क्षेत्र के उपेक्षित रह गया। चार प्रमुख तीर्थ केन्द्र इस प्रदेश में हैं। विश्व का सातवां आश्चर्य ताजमहल इसी प्रदेश में है। भगवान बुद्ध की तपो भूमि अधिकांश रूप में उत्तर प्रदेश में है। पवित्र गंगा–यमुना का संगम इसी प्रदेश में है। समस्त विश्व के हिन्दुओं की श्रद्धा का केन्द्र–बिन्दु काशी विश्वनाथ मन्दिर इसी प्रदेश में है। प्रसिद्ध सूफियों की दरगाहें , स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केन्द्र, सब यहीं पर हैं। इसके बाद भी

सौजन्य से- उत्तर प्रदेश सरकार

पर्यटक उत्तर प्रदेश में केवल ताजमहल का भ्रमण करते हैं।

बीते ढाई वर्षों में प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य हुआ है। सड़क कनेक्टिविटी, आतिथ्य उद्योग के विकास, हवाई सेवा से सम्बद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने से पर्यटन उद्योग के स्वरूप में 10 गुना वृद्धि हुई है। प्रयागराज कुम्भ की ब्रांडिंग से 49 दिनों के समागम में लगभग 25 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रयागराज का भ्रमण किया। प्रयागराज कुम्भ में स्वच्छता, बस सेवा एवं पेंट माय सिटी अभियान के तीन विश्व रिकार्ड कायम हुए जिसने पूरे विश्व का ध्यान इस आयोजन की ओर खींचा।

इसी तरह अयोध्या दीपोत्सव में 3.31 लाख दीये प्रज्ज्वलित करके विश्व रिकार्ड बनाया गया। साथ ही पर्यटन के नये आयाम भी खुल रहे है। इसी तरह मथुरा में कृष्णोत्सव एवं रंगोत्सव का भव्य आयोजन कर विश्व भर के कृष्ण भक्तों को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित कर पर्यटन को बढ़ाया जा रहा है। बौद्ध सर्किट को विकसित कर बौद्ध पर्यटन को भी एक बड़े पर्यटन उद्योग में बदला जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद अपने-अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए जाने जाते हैं, परन्तु उनकी इस क्षमता का उपयोग कभी नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश की इस क्षमता को विश्वपटल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट यानी ओ.डी.ओ.पी. योजना प्रस्तुत की, जिसके चलते हर जिले के विशिष्ट उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और नया बाजार मिलने के कारण जिलावार उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग के साथ ही रोजगार में वृद्धि हुई। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1 हजार करोड़ रु. से अधिक के ऋण वितरित कर इसे गति दी गयी। इस योजना का समन्वित परिणाम राज्य की अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प व स्वरोजगार के विस्तार के रूप में मिल रहा है। प्रदेश का निर्यात बढ़ा है।

बुन्देलखण्ड में विकास के लिए विगत कई वर्षों से बहुत बातें हुईं, परन्तु धरातल पर कुछ न होने के कारण बुन्देलखण्ड धीरे-धीरे पलायन का शिकार हो गया था। योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। गर्मियों में पेयजल की व्यवस्था करना, किसानों को सिंचाई सुविधा देना, जल-संरक्षण के लिए खेत-तालाब योजना चलाना, बुन्देलखण्ड के लिए अभिशाप अन्ना प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था करना और रोजगार के

- **प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर अग्रसर।**
- **इंसेफ्लाइटिस के मामलों में 35% की कमी आयी है और मौत के आंकड़ों में 65% की गिरावट हुई है।**
- **297 किमी. लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का विकास किया जा रहा है।**

लखनऊ में आयोजित इनवेस्टर्स समिट - 2018 में उद्योगपतियों के साथ मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

अवसर बढ़ाना इस सरकार की बड़ी उपलब्धियों में है, इससे बुन्देलखण्ड से पलायन समाप्त हुआ है।

बुन्देलखण्ड में स्थायी रोजगार सृजन के लिए वहां पर 20 हजार करोड़ रूपये के निवेश से डिफेंस कारिडोर की आधारशिला रखी गयी है, जिसके विकसित होने पर ढाई लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा वहां पर चित्रकूट से इटावा तक 07 जनपदों से होकर गुजरने वाले 297 कि0मी0 लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे का भी विकास किया जा रहा है, जिससे बुन्देलखण्ड की कनेक्टिविटी आगरा और लखनऊ से सुगम हो जायेगी।

बच्चे देश के भविष्य होते हैं, परन्तु पूर्वांचल के बच्चों को पिछले वर्षों में इंसेफ्लाईटिस का ग्रास बनने के लिए छोड़ दिया गया था। राज्य के 38 जनपदों में हर बारिश और उसके बाद होने वाली नमीपूर्ण ठंड में यह महामारी के रूप में फैलता था। पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद से ही इस पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया। इसके परिणामस्वरूप इन रोगों के मामलों में 35 फीसद की कमी हुई है और मौत के आंकड़ों में 65 प्रतिशत की गिरावट आई है।

इस तरह सुशासन के बेमिसाल ढाई साल व्यतीत हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इंवेस्टर्स समिट में देश के शीर्ष उद्योगपतियों की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य दिया था। प्रधानमंत्री जी को साफ दिख रहा था कि प्रदेश में नई सरकार के आठ माह के कार्यकाल में ही देश के दिग्गज उद्योगपति जब यहां उपस्थित हो गये हैं तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह प्रदेश वन ट्रिलियन डालर इकोनोमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और इसीलिए उन्होंने वन ट्रिलियन डालर इकोनोमी का लक्ष्य दिया।

अनुक्रमणिका

भारत सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां	2
उत्तर प्रदेश देश में नम्बर–1	15
कानून–व्यवस्था : सख्त कदम – अपराधियों में खौफ	17
खेती–किसानी पर फोकस	20
ग्राम्य विकास : परफार्मेन्स इंडेक्स में प्रथम	22
राजस्व : खेतों की मेड़ों तक तकनीक	24
मेडिकल सुविधाओं का नया युग	27
शिक्षा की अलख	30
घर–घर बिजली	32
इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार	34
औद्योगिक विकास का नया सवेरा	37
नगर : स्वच्छता के लिए सम्मान	38
श्रमिकों के अच्छे दिन	39
समाज कल्याण : सम्मानजनक जीवन के रास्ते खुले	40
पशुपालन एवं दुग्ध विकास	42
पर्यटन एवं संस्कृति में ऊँचे आयाम	44
सूचना प्रौद्योगिकी	46
आस्था को नमन	47
वन एवं पर्यावरण	48
महिला सशक्तिकरण	50
खेलोगे तो बढ़ोगे	52
कैबिनेट द्वारा जनहित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय	54
सोशल मीडिया संदेश	62
सफलता की कहानी : लाभार्थियों की जुबानी	71
मीडिया कवरेज	73

भारत सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां

ऐतिहासिक निर्णयः जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाया गया

- मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू–कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटा दिया है। संविधान के अनुच्छेद 35ए को निरस्त कर दिया गया है।
- भारतीय संविधान के सभी प्रावधान अब से जम्मू–कश्मीर पर भी लागू होंगे।

समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना

- विवाहित मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत – तीन तलाक की रूढ़िवादी प्रथा समाप्त।

सौजन्य से- उत्तर प्रदेश सरकार

बाल अधिकारों का संरक्षण– पॉक्सो अधिनियम में संशोधन

- पॉक्सो अधिनियम में संशोधन करते हुए बाल यौन अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान।
- पॉक्सो से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

- ट्रांसजेंडर को भेद–भाव से बचाने के लिए उनके अधिकारों को परिभाषित किया गया।
- जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए 150 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मंजूर किए गए।
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान–धन योजना–2019 को मंजूरी। 60 वर्ष की आयु होने पर व्यापारी को 3000 रु. मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन।
- अवैध जमा योजनाओं से गरीब और भोले–भाले नागरिकों की रक्षा हेतु अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019।

किसानों की आमदनी दोगुनी करने की ओर ठोस कदम

- पी.एम. किसान योजना में अब सभी किसान सम्मिलित किए गए।
- पी.एम. किसान योजना के विस्तार से 14.5 करोड़ किसानों को लाभ। 20520 करोड़ रुपये अंतरित किए गए।
- पी.एम. किसान मान धन योजना के तहत पहले 3 वर्षों में 5 करोड़ लघु और सीमान्त किसानों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
- इसके तहत 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले किसानों को न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जायेगी।

➢ **40 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक**

- 1674 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चीनी का बफर स्टॉक तैयार किया जायेगा। चीनी मिलों द्वारा किसानों के खातों में सीधे भुगतान किया जाएगा।
- अतिरिक्त 60 लाख टन चीनी का निर्यात भी किया जायेगा।
- जैव ईंधन इथेनाल का प्रयोग किया जायेगा।

➢ **खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि**

- इसके तहत किसानों को लागत से 1.5 गुना भुगतान किया जायेगा।

सभी का सशक्तिकरण

- ग्रामीण इलाकों में पात्र लाभार्थियों के लिए 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण कराया जायेगा।
- शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 23400 करोड़ रु. का निवेश। केन्द्रीय सहायता से शहरों में 4.26 लाख मकानों का निर्माण कराया जायेगा।
- आजादी के 75वें वर्ष 2022 में गांवों में रहने वाले प्रत्येक एकल परिवार के लिए एक बिजली कनेक्शन और एक स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा।
- जल–जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल मुहैया कराया जायेगा।

➢ **आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** के तहत 16085 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया, 41 लाख लाभार्थियों को भर्ती किया गया और 10 करोड़ ई–कार्ड जारी किये गये।

- आयुष्मान भारत के तहत 20700 से अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं।

➢ **एक देश एक राशन कार्ड**

- आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में अन्तर्राज्यीय पोर्टबिल्टी लागू कर दी गयी है।

अन्य राज्यों में भी योजना लागू की जायेगी।

➢ **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**

- 100 दिनों के अन्दर 8 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया गया है। 80 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को जोड़ा गया। पांच किलो के रिफिल लेने वालों की संख्या 489322 पहुंची।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 16,494 स्वयं सहायता समूहों का गठन

अवस्थापना और निवेश पर फोकस

- अगले 5 वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
- 2000 करोड़ रुपये की लागत से 143 किलोमीटर लम्बी बोंगाईगांव–अगथोरी रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी।
- 2650 करोड़ रुपये की लागत से प्रयागराज और पं0 दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच तीसरी रेलवे लाइन की मंजूरी।
- 1320 करोड़ रुपये से दोहरी घाट और सहजनवा के बीच नई रेलवे लाइन स्वीकृति।
- रेलवे को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बनाने के लिए 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा
- दिल्ली–मुम्बई और दिल्ली–हावड़ा रूटों पर 2023 तक गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जायेगा।
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 609 करोड़ रुपये की लागत से 88 परियोजनायें पूर्ण, 2778 करोड़ रुपये की लागत की 153 नई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर।
- 'एक शहर : एक प्रभाव कार्यक्रम' के तहत 100 स्मार्ट शहरों में 2.7 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

जल शक्ति मंत्रालय का गठन

- जल सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने के लिए नवगठित जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और जल संरक्षण जन आन्दोलन के रूप में चलाया जा रहा है।
- 7.23 लाख प्राकृतिक जलाशयों/स्रोतों का प्रबंधन।

उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर फोकस

- राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद कानून 2019 लागू
- 25 नये सरकारी मेडिकल कालेजों में 2750 अतिरिक्त सीटें बढ़ायी गयी।
- 75 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना से देश में 15,700 एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी।

सड़क सुरक्षा : सुगम परिवहन

- प्रभावशाली, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 लागू किया गया है।
- बिजली से चलने वाले वाहनों (ईवी) पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
- ईवी के चार्जर पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

दुनिया का कहना है भारत दिन पर दिन स्वच्छ हो रहा है।

यूनीसेफ के अध्ययन के अनुसार स्वच्छ भारत पहल के कारण भू–जल का प्रदूषण कम हुआ है। भारत के अनेक हिस्से खुले में शौच से मुक्त हुये हैं।

योग दिवस एवं फिट इण्डिया अभियान

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता दिलायी गयी।
- 170 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है।
- राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री फिट इण्डिया अभियान की शुरू की।

देश की रक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को समर्पित फैसला

विश्व में भारत का कद बढ़ा

विश्व ने किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सम्मान

- मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान **'आर्डर ऑफ जायद'** प्रदान किया गया।
- मा. प्रधानमंत्री जी को रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार **'आर्डर ऑफ सेंट एन्ड्रयू द अपॉसल'** दिया गया।

➢ आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में ठोस पहल

- प्रधानमंत्री ने जी–20, ब्रिक्स तथा एससीओ शिखर सम्मेलनों में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर राय बनाने में अहम भूमिका निभायी।

➢ मजबूत हुये भारत और अमेरिका के सम्बन्ध

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में दोनों नेताओं के बीच 5जी,व्यापार, ईरान और सुरक्षा संबंधों जैसे विविध मुद्दों पर व्यापक विचार–विमर्श हुआ।

➢ मित्र देश भूटान की यात्रा

- मा. प्रधानमंत्री जी ने भूटान का दौरा कर 720 मेगावाट पनबिजली परियोजना, दक्षिण एशिया उपग्रह, भू–स्टेशन, रुपे कार्ड, भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का शुभारंभ किया।

➢ श्रीलंका यात्रा

- पड़ोसी देशों से मजबूत सम्बन्ध बनाने की दिशा में मा. प्रधानमंत्री जी ने श्रीलंका की यात्रा की।

➢ यूएई में भी भारतीय रूपे कार्ड की शुरूआत

- प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमीरात की यात्रा के दौरान भारतीय रूपे कार्ड का शुभारंभ किया।

- **फ्रांस यात्रा से रणनीतिक सम्बन्धों में मजबूती**
  - मा0 प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस का दौरा करके भारत–फ्रांस देशों के सम्बन्धों को और मजबूत किया है।

बड़े आर्थिक सुधार

- सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए गए।
- कंपनियों, रिटेल, एम.एस.एम.ई., छोटे व्यापारी एवं अन्य लोगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को 70,000 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई।
- गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं आवास वित्त कंपनियों को सहायता।
- रेपो रेट को ब्याज दर से जोड़कर आवास ऋण, वाहन ऋण इत्यादि के ई.एम.आई. को कम किया गया।
- ढांचागत ऋण सुलभ कराने के लिए एक नया संगठन बनाया जाएगा।
- ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत देने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए।

कारोबार में सुगमता

- सीएसआर का उल्लंघन अब दीवानी मामला माना जाएगा।
- कर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
- दीर्घकालिक/अल्पकालिक पूँजीगत लाभ पर बढ़े हुए सरचार्ज को समाप्त कर दिया गया है।
- ऋण अदायगी समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर बैंक को ऋण दस्तावेजों को वापस करना अनिवार्य । ग्राहकों द्वारा ऋण आवेदनों की आनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रारम्भ।
- एम.एस.एम.ई. के सभी लम्बित् जी.एस.टी. रिफण्ड का भुगतान 30 दिनों के भीतर करने की व्यवस्था लागू। एम.एस.एम.ई. और रिटेल या छोटे ऋण लेने वालों के लिए बेहतर पारदर्शी वन टाइम सेटेलमेंट की व्यवस्था।

स्टार्ट–अप्स को बढ़ावा

- स्टार्ट–अप्स के लिए एंजेल टैक्स प्रावधानों को वापस।
- आयकर रिटर्न दाखिल करने में पैन कार्ड और आधार कार्ड की परस्पर अदला–बदली की अनुमति
- आयकर रिटर्न के मामलों में जाँच में व्यक्तिगत उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त।

श्रम कानून

- ईएसआईसी में अंशदान 6.5 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत किया।
- स्टार्ट–अप्स के लिए 6 श्रम कानूनों में स्व–प्रमाणन सुविधा।
- एमएसएमई द्वारा किसी कारखाने की स्थापना के लिए एकल सहमति।
- कॉरपोरेट मामलों में 16 अपराध धारायें आर्थिक दंड में परिवर्तित। 14,000 से भी अधिक मुकदमों को वापस लिया गया।
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में कई संशोधनों को मंजूरी।
- बॉन्ड बाजारों को मजबूती देने के कदम।
- वैश्विक बाजारों में भारतीय कंपनियों की पहुंच हेतु कदम।
- घरेलू छोटे निवेशकों के लिए केवाईसी के लिए आधार के प्रयोग की अनुमति।
- विदेशी निवेशकों और एफपीआई के लिए सरल केवाईसी।

- पाँच वर्षों में आधुनिक बुनियादी ढांचे हेतु 100 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं हेतु अंतर–मंत्रालय कार्यबल का गठन।
  - कॉरपोरेट टैक्स में कमी करने का निर्णय।
- विभिन्न सेक्टर्स पर एफडीआई नीति की समीक्षा को मंजूरी
  - विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू ।
  - राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना।
  - व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद तथा व्यापार बोर्ड का विलय किया गया।

पर्यटन

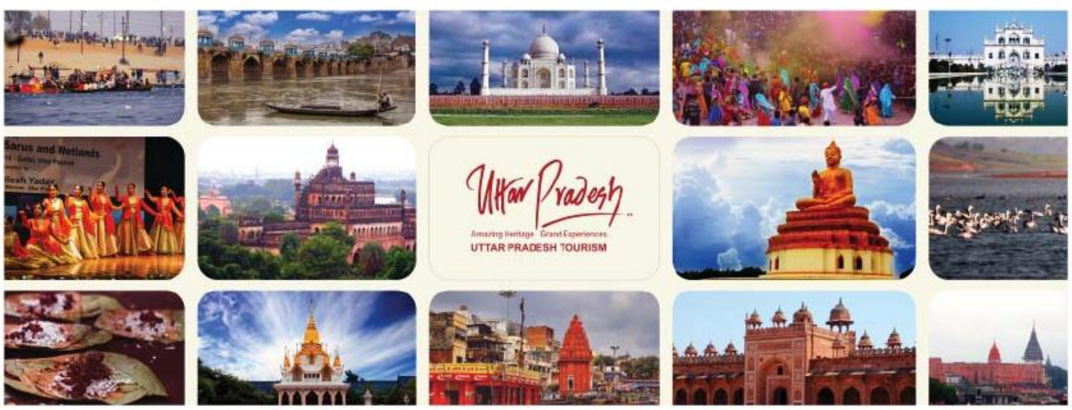

- 597 फुट ऊँची सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा, "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में देश के एक नये पर्यटन स्थल का विकास।
- विदेशी पर्यटक 4 राज्यों की 137 पर्वत चोटियों पर पर्वतारोहण और ट्रैकिंग कर सकेंगे।

सतत विकास लक्ष्य विजन 2030

उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित सतत विकास- लक्ष्य- विजन 2030 को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गांधी जयन्ती 2 अक्टूबर, 2019 से उत्तर प्रदेश विधान सभा का 48 घंटे का अनवरत सत्र आहूत किया गया है, जो सतत विकास-लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक अविस्मरणीय चर्चा का केन्द्र बिन्दु होगा।

आई.आई.एम. लखनऊ में मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों के साथ मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य
(MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL)

सतत विकास लक्ष्य एक साहसिक कार्य है जो सबके लिए एक समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज की सृष्टि करेगा। 16 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 टार्गेट हैं।

क्र0सं0	सतत विकास	लक्ष्य	नोडल विभाग
1.	गरीबी उन्मूलन	No Poverty	ग्राम्य विकास
2.	भुखमरी समाप्त करना	Zero Hunger	कृषि
3.	सभी के लिए स्वस्थ जीवन	Good Health and Well being	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
4.	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	Quality Education	माध्यमिक शिक्षा
5.	लैंगिक समानता	Gender Equality	महिला कल्याण
6.	सुरक्षित जल एवं स्वच्छता का सतत् प्रबन्धन	Clean Water & Sanitation	जल शक्ति
7.	किफायती, सतत् और आधुनिक ऊर्जा	Affordable & Clean Energy	ऊर्जा
8.	उचित कार्य एवं आर्थिक विकास	Descent Work & Economic Growth	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
9.	उद्यमिता, अभिनवीकरण एवं अवस्थापना	Industry, Innovation & Infrastructure	औद्योगिक विकास
10.	असमानता कम करना	Reduced ineqalities	समाज कल्याण
11.	समावेशी एवं सुरक्षित शहर	Sustainable Cities & Communities	नगर विकास
12.	सतत् उपभोग एवं उत्पादन	Responsible Consumption & Production	पर्यावरण
13.	जलवायु परिवर्तन	Climate Action	पर्यावरण
14.	भूमि पर जीवन	Life on Land	वन
15.	शान्तिपूर्ण एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण	Peace, Justice & Strong Institutions	गृह
16.	लक्ष्यों के लिए भागीदारी	Partnerships for Goals	वित्त

सतत विकास लक्ष्य के मुख्य सिद्धान्त

एस0डी0जी0 के मुख्य सिद्धान्त जन, सम्पन्नता, शान्ति, साझेदारी एवं पृथ्वी पर आधारित हैं।

सतत विकास लक्ष्य-2030, उत्तर प्रदेश (प्रगति)

प्रदेश के 64 विभागों को सम्मिलित करते हुए विजन डाक्यूमेंट–2030 तैयार किया गया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्न हैः–

- सबका सतत एवं स्थायी विकास
- कमजोर वर्गों को प्राथमिकता
- सुशासन–न्यायिक एवं सुरक्षित वातावरण
- अवसरों का सृजन
- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण
- पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण

● लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 03 वर्षीय (2017–18, 2018–19 तथा 2019–20) कार्ययोजना तैयार की गयी है। ● समस्त एस0डी0जी0 गोल्स एवं उनके टार्गेट के सापेक्ष योजनाओं/कार्यक्रमों की मैपिंग की गयी है। ● गुणवत्तायुक्त सूचनायें संकलित करने हेतु निरन्तर सलाहकारी बैठकें आयोजित की गयीं। ● राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी। ●नोडल विभागों द्वारा भी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ● प्रदेश हेतु एस0डी0जी0 बेसलाइन रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। ● पंचायत स्तर पर एस0डी0जी0 लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गतिविधियों एवं रणनीतियों की पहचान एवं निर्धारण किया जा चुका है। ● सतत विकास–लक्ष्य के दृष्टिगत जिला एवं मण्डल स्तर पर मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक अनुश्रवण प्रक्रिया के अन्तर्गत 85 इंडीकेटर्स विकसित किये गये हैं। ● मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा।

देश में नम्बर

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) में 25 लाख से अधिक आवास बनाकर प्रथम स्थान पर

73 हजार करोड़ रुपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कर प्रथम स्थान पर

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 1.35 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान कर प्रथम स्थान पर

ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को शौचालय देकर देश में प्रथम स्थान पर।

सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना में प्रथम स्थान पर

किसानों को देय अनुदान को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में पहला राज्य।

सौभाग्य योजना एवं अन्य योजनाओं में **1 करोड़ 9 लाख विद्युत कनेक्शन** देकर देश में **प्रथम स्थान** पर

सर्वाधिक **चिकित्सा शिक्षण संस्थान** स्थापित कर उन्हें संचालित करने में पूरे देश में अग्रणी

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं **आम आदमी बीमा योजना** में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर।

ई-टेन्डरिंग प्रणाली में सर्वोत्तम परफार्मेन्स के लिए **उत्तर प्रदेश बेस्ट परफार्मेन्स एवार्ड** से सम्मानित

मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का प्रथम राज्य

मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य

दुग्ध, चीनी, गन्ना एवं **आम उत्पादन** में प्रथम स्थान पर

राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य।

कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य

ई-मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने वाला देश का पहला राज्य जिसे केन्द्र से पुरस्कार मिला।

सड़क व हवाई कनेक्टीविटी में सर्वश्रेष्ठ।

सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं **पारदर्शिता** में अग्रणी राज्य।

औद्योगीकरण के लिए **भूमि उपलब्धता व आवंटन** में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल।

अटल पेंशन योजना में देश में प्रथम स्थान पर

सख्त कदम अपराधियों में खौफ

पूर्व की अराजकता को समाप्त कर अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त वातावरण सृजित करने के लिए प्रदेश सरकार ने कानून–व्यवस्था पर जीरो टालरेन्स नीति अपनाई। अपराधों को शत–प्रतिशत दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए। पहली बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफ.आई.आर काउन्टर खोले गए। अपराधों पर नियंत्रण से प्रदेश में कानून का राज पुनः स्थापित हुआ, जिससे विकास का माहौल कायम हुआ। प्रदेश में सभी प्रमुख पर्व, त्यौहार, मेले और अन्य धार्मिक आयोजन तथा इस साल लोकसभा चुनाव भी सकुशल सम्पन्न हुए।

- अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कारवाई के कारण 16,375 अपराधियों द्वारा स्वयं जमानत निरस्त कराकर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया।
- विगत ढाई वर्षों में पुलिस और अपराधियों के बीच 4604 मुठभेड़ें हुईं, जिनमें 10098 अपराधी गिरफ्तार किये गये, 1571 घायल हुए तथा पुलिस की आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 94 अपराधी मारे गये। पुलिस कार्यवाही के दौरान 742 पुलिस कर्मी घायल एवं 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए।
- भू–माफिया एवं अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा अवैध रुप से अर्जित लगभग 01 अरब, 94 करोड़ 48 लाख रु. की सम्पत्ति जब्त की गयी।

- **वर्ष 2017 की तुलना में प्रदेश में वर्ष 2018 में गम्भीर अपराधों जैसे डकैती, बलात्कार,हत्या, अपहरण एवं लूट के अपराधों में कमी आयी है। डकैती में 53.7 प्रतिशत, बलात्कार में 35.06 प्रतिशत, हत्या में 14.05 प्रतिशत, लूट में 44.5 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण में 30.43 प्रतिशत, बलवा में 38.1 प्रतिशत की कमी आयी है।**

- प्रदेश में पहली बार हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया। बेहतर पुलिसिंग के कारण आज सार्वजनिक स्थानों से अराजक तत्वों का पलायन हुआ है और माताएँ, बहनें और बेटियाँ निर्भीक होकर घर से बाहर निकलकर अपना भविष्य सँवार रही हैं।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ टेलीफोन के माध्यम से छेड़खानी व विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न तथा अपराधों को रोकने के लिए स्थापित **1090 सेवा** में **2,66,005 शिकायतें** प्राप्त हुईं, इनमें से **98.80 प्रतिशत शिकायतों** का निस्तारण किया गया।
- समस्त जनपदों में **आपरेशन आत्मरक्षा** चलाया गया। इसके तहत लगभग **573308 छात्राओं** को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर सी0एम0 **हेल्पलाइन टोल फ्री नं0 1076** संचालित है, जिस पर एक काल से ही गांव, शहर, कस्बे से कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत, समस्या या सुझाव दर्ज करा सकता है। इसके अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं में से 100 सूचनाओं का चयन मा0 मुख्यमंत्री द्वारा करके उनकी समीक्षा की जाती है। यह हेल्पलाइन 24X7 घण्टे जनता के लिए उपलब्ध है।

मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, लोक भवन में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन '1076' का 'लोगो' लांच करते हुए। दिनांक 04 जुलाई 2019, लखनऊ। (चित्र सू0वि0)

- **लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 के दौरान देश की सबसे बड़ी आबादी वाले इस प्रदेश के 1 लाख 63 हजार बूथों पर 7 चरणों में निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न हुआ, जबकि इससे छोटे कई राज्यों में मतदान के दौरान हिंसा व अन्य बाधाओं के चलते पुनर्मतदान तक हुआ। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य जहां पूर्व के चुनावों में हिंसा और मतदान में बाधा का लम्बा इतिहास रहा हो, वहां इस बार शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न होना प्रदेश की सुधरी एवं सुदृढ़ कानून–व्यवस्था को परिलक्षित करता है।**

- एस.टी.एफ. द्वारा 19 मार्च, 2017 से 30 जनवरी, 2019 तक 1815 अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी। इनमें 174 इनामी अपराधी, 1198 दुर्दान्त अपराधी व संगठित अपराधी, 64 वन्य जीव अपराधी तथा 269 मादक पदार्थ तस्कर एवं 217 साइबर अपराधी शामिल हैं।

पुलिस विभाग का सुदृढ़ीकरण

- लखनऊ में पुलिस मुख्यालय की **सिग्नेचर बिल्डिंग** का लोकार्पण किया गया।
- पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए 41 नए थाने, 13 नई चौकियाँ, 58 नए अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये गये। 75 एण्टी पावर थेफ्ट पुलिस थानों की भी स्थापना की गईं।
- 1 लाख से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। अब तक 79,675 नई भर्तियां की जा चुकी हैं।
- विभिन्न पदों में वरिष्ठता के आधार पर 45,568 पदों पर पदोन्नति की गयी।
- नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं में यूपीकॉप (UPCOP) मोबाइल ऐप तथा ई–एफआईआर की व्यवस्था की गई।
- स्पेशल पुलिस ऑपरेशन्स टीम (SPOT) का गठन किया गया।
- पुलिस के शहीदों के आश्रितों को अनुग्रह राशि रु. 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये की गयी।
- शहीद पुलिसकर्मियों के माता–पिता को अनुग्रह राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गयी।
- होमगार्ड कल्याण निधि रु. 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गयी।

नवनिर्मित पुलिस मुख्यालय (सिग्नेचर बिल्डिंग) का लोकार्पण करते हुए मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

सोशल मीडिया

- सोशल मीडिया के माध्यम से फैलायी जाने वाली अफवाहों को रोकने के लिए प्रदेश के समस्त थानों पर **डिजिटल वॉलेन्टियर** के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाये गये, जिनके माध्यम से अब तक लगभग 2 लाख 40 हजार लोगों को डिजिटल वॉलेन्टियर बनाया गया।

खेती-किसानी पर फोकस

किसानों की आय में वृद्धि प्रदेश की खुशहाली का आधार है।
कृषि और किसानों को केन्द्र में रखकर प्रदेश सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए।

किसानों के हित में फैसले

- रु. 36,000 करोड़ से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का ऋण मोचन।
- किसानों को रु. 73 हजार करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया, जो पिछली दो सरकारों के 10 साल के कार्यकाल में हुए भुगतान से ज्यादा है।
- फसलों की नई प्रोक्योरमेण्ट पॉलिसी लागू।
- 50 लाख से अधिक किसानों को **1 हजार 222 करोड़ रु.** की धनराशि का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया गया।
- गेहूं की एमएसपी को रु. 1735 से बढ़ाकर रु. 1840 प्रति कुंतल किया गया।
- धान कॉमन एवं ए-ग्रेड की एमएसपी में वृद्धि कर क्रमशः रु. 1815 प्रति कुंतल एवं रु. 1835 प्रति कुंतल किया गया।
- 5500 सरकारी क्रय केन्द्रों के माध्यम से 126 लाख मी. टन गेहूँ और 101 लाख मी. टन धान की रिकार्ड खरीद सीधे किसानों से की गई। प्रदेश में पहली बार दलहन, तिलहन एवं मक्का का समर्थन मूल्य तय करते हुए इनकी सीधी खरीद।
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के 2 करोड़ 33 लाख किसान परिवारों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 1 करोड़ 57 लाख किसानों को प्रथम किस्त के रूप में रु. 4364.57 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित की गई।
- किसानों को **4 करोड़** से अधिक **मृदा स्वास्थ्य कार्ड** वितरित।
- 71 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित।
- किसान पाठशाला **(द मिलियन फार्मर्स स्कूल)** के माध्यम से 30 लाख से अधिक किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक में प्रशिक्षित किया गया।
- पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के **''कृषि कुम्भ''** का आयोजन किया गया, जिसमें एक लाख किसानों ने सहभागिता की।
- 166 ई-नाम मण्डियां स्थापित की गईं। इनसे 53.9 लाख किसानों को जोड़ा गया।
- विगत ढाई वर्षों में 1 लाख 64 हजार 577 करोड़ रु. का फसल ऋण वितरित किया गया।
- विगत ढाई वर्षों में 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई जबकि वर्ष 2014 से 2016 के बीच केवल 1 कृषि विज्ञान केन्द्र ही स्थापित किया जा सका था।

जल की महत्ता पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते जल संकट को ध्यान में रखते हुए पानी की बर्बादी रोककर इसके बूँद-बूँद के सदुपयोग का संकल्प व्यक्त किया है। इसी दिशा में दूरगामी कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जल शक्ति विभाग का गठन किया गया है।

- वर्षों से अधूरी पड़ी बाण सागर, पहुंज बांध, पथरई बांध, पहाड़ी बांध, लहचुरा बांध, गुंटा

बांध, मौदहा बांध तथा जमरार बांध आदि परियोजनाओं को वर्तमान सरकार ने पूरा किया।

- इन परियोजनाओं पर 4,332.91 करोड़ रु. व्यय किया गया और इनके पूर्ण होने से 2 लाख 66 हजार 666 हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई तथा 2.35 लाख किसानों को लाभ मिला।
- 14 अन्य सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का कार्य किया जा रहा है। इनमें अर्जुन सहायक, भावनी बांध, रसिन बांध, लखेरी बांध, रतौली वियर, जाखलोन पम्प नहर की क्षमता की पुनर्स्थापना, जाखलोन पम्प नहर 250 सोलर पावर प्लांट, सरयू नहर, मध्य गंगा, उत्तर प्रदेश वाटर रीस्ट्रक्चरिंग, बंडई बांध, मझगाँव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, कुलपहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना पर 20686 करोड़ रु. व्यय कर 9.95 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा। इससे 18.51 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
- विभिन्न नदियों पर 3869 किमी. लम्बाई के 523 तटबन्धों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण किया गया।
- बुन्देलखण्ड में 8384 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया। इस वर्ष बुन्देलखण्ड के जनपदों में 6558 खेत–तालाबों का निर्माण कराया जायेगा।
- 50 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई योजना से लाभान्वित किया गया।
- 74811 निःशुल्क बोरिंग करते हुए 161485 हेक्टेयर सिंचन क्षमता बढ़ोतरी की गयी।

राशन : वितरण की कालाबाजारी पर अंकुश

प्रदेश सरकार ने आम जन को भरपूर अनाज उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राशन दुकानों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराया। साथ ही फर्जी राशन कार्डों को निरस्त करने की कार्यवाही भी की गई। इससे अनाज वितरण में गोलमाल पर अंकुश लगा।

- विगत ढाई वर्षों में हर गांव और शहर में अभियान चलाकर राशन कार्डों का सत्यापन किया गया, जिसमें 63 लाख से अधिक फर्जी पाये गए राशन कार्डों को निरस्त किया गया।
- 3 करोड़ 55 लाख परिवारों को नये राशन कार्ड वितरित किए गए और लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन की दुकान चुनने का अवसर दिया गया।
- लाभार्थियों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए ई–पास मशीनों के माध्यम से सुचारु खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
- ई–पास टेक्नोलॉजी के प्रयोग से **1100 करोड़ रु.** से अधिक की बचत सम्भव हुई।

ग्राम्य विकास

परफार्मेन्स इंडेक्स में प्रथम

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के परफार्मेन्स इंडेक्स में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है।

ग्रामीण क्षेत्र में आवास की भारी मांग के दृष्टिगत आवासों का निर्माण जितनी तेजी से हो रहा है वह अभूतपूर्व है। अब तक स्वीकृत 12.82 लाख आवासों के सापेक्ष 12.45 लाख आवास पूर्ण कर पात्र लोगों को दे दिए गए है। इस वित्तीय वर्ष में 1.54 लाख आवासों का निर्माण प्रगति पर है।

प्रतिबद्धता एवं गतिशीलता के कारण उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण में देश में प्रथम स्थान पर रहा।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7023 गरीब मुसहर परिवारों को आवास दिया गया।
- **पहली बार वनटांगिया, मुसहर, कोल, थारू जनजाति के 38 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया, जिससे वन क्षेत्रों में बसे इन गांवों के गरीबों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली एवं राशन कार्ड आदि मूलभूत सुविधाएं मिल सकीं।**
- मनरेगा में अब तक 2733.56 करोड़ रू0 व्यय कर 14.85 करोड़ मानव दिवसों का सृजन।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल 1621 स्वयं समूहों का गठन।
- कुल 7240 समूहों को रुपये 15000 प्रति समूह की दर से रिवल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया गया। 4991 समूहों को रूपये 110000 प्रति समूह की दर से सामुदायिक निवेश उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त कुल 2965 समूहों को बैंक लिंकेज से भी जोड़ा गया।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 6003 कि.मी. सड़कों का निर्माण पूर्ण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को व्यक्तिगत शौचालयों से आच्छादित किया गया।
- बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र के अवशेष 5720 ग्रामों हेतु शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए बुन्देलखण्ड/ विन्ध्य क्षेत्र में कुल 441 भूमिगत/सतही स्रोतों पर आधारित योजनाएं बनायी जानी है, जिससे 77.65 लाख आबादी लाभान्वित होगी। उक्त पर कुल रूपये 15722.89 करोड़ व्यय होने का अनुमान है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 16700 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में सामान्य वर्ग के 4498, अनुसूचित जाति के 29360 एवं अनुसूचित जन जाति के 159 लाभार्थी, इस प्रकार कुल 34017 लाभार्थियों को आवास देकर लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य।
- गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 से संचालित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना प्रदेश के 16 जनपदों में क्रियाशील।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 512 परियोजनाएं पूर्ण।
- नीर निर्मल परियोजना के अन्तर्गत 9 जनपदों में 221 परियोजनाओं तथा बैच 2 के अन्तर्गत 592 ग्राम पंचायतों हेतु 379 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनपद महराजगंज के वनटांगिया ग्रामों में जनकल्याणकारी विकास कार्यों का शुभारम्भ करते हुए। दिनांक 01 जनवरी, 2018

राजस्व : खेत की मेड़ों तक टेक्नोलॉजी

गांवों की सुख-शान्ति अविवादित वरासतों, खेतों के फूलप्रूफ नक्शे, सही पैमाइश, फसलों की क्षति के सही मुआवजे आदि पर निर्भर है। प्रदेश सरकार द्वारा अविवादित वरासतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है और अब कहीं से भी ऑनलाइन वरासत अंकित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। इसी तरह सह खातेदारों के अंश का निर्धारण करने में त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है। कृषि योग्य भूमि के सभी गाटों को एक यूनीक कोड देने के लिए भू लेख पोर्टल को निबन्धन विभाग, राजस्व न्यायालय, कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली एवं भू नक्शा पोर्टलों से लिंक कर दिया गया है। पैमाइश को आसान बनाने के लिए तहसीलदार /नायब तहसीलदार को भी अधिकृत किया गया है।

- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संशोधन करके किसानों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
- **अविवादित वरासत** के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने हेतु आनलाईन पोर्टल संचालित किया गया। अब किसी भी कृषक की मृत्यु पर उसके वारिसों द्वारा कहीं से भी आनलाइन वरासत अंकित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है, जिसका निस्तारण एक माह में करना अनिवार्य है। यदि राजस्व निरीक्षक की जांच में वरासत विवादित पायी जाती हैं तो सम्बन्धित न्यायालय में स्वत: वाद पंजीकृत करके कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

इससे प्रदेश के लाखों लोगों को अनावश्यक रूप से तहसील के चक्कर लगाने से छूट मिल गयी है।

- अभी तक इस पोर्टल पर 85,946 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 57,069 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए वरासत अंकित की जा चुकी है।
- **हैसियत प्रमाण–पत्र** के लिए भी आवेदन आनलाईन किया जा सकता है, जिसका 30 दिन के अन्दर जिला प्रशासन को निस्तारण करना अनिवार्य है। इस व्यवस्था से सम्बन्धित व्यक्तियों को अनावश्यक उत्पीड़न से काफी हद तक मुक्ति मिली है। पोर्टल पर अभी तक 24655 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 9,692 प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते हुए हैसियत प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं।
- **एण्टी भू–माफिया** अभियान के अन्तर्गत जिलास्तर पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, अब तक 2,67,773 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है और 57,491 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। 1664 अतिक्रमण–कर्ताओं को भू–माफिया के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनमें से वर्तमान में 164 भू–माफिया जेल में निरुद्ध हैं।
- जनपद बाराबंकी में 3849 हे0, प्रयागराज में 3551 हे0, पीलीभीत में 2381 हे0, सिद्धार्थनगर में 2302 हे0 व बिजनौर में 2201 हे0 भूमि अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी।
- **सह खातेदारों के अंश निर्धारण** का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 34,613 ग्रामों के अंश–निर्धारण का कार्य पूरा हो चुका है।
- वर्तमान में 15,405 राजस्व ग्रामों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य प्रचलित है। इस प्रक्रिया में खतौनी की लिपिकीय त्रुटि जैसे खातेदार का नाम, क्षेत्रफल आदि भी ठीक किया जा रहा है, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी आयी है।
- अब तक 891701 आधार सीडिंग सम्बन्धित खातों के सापेक्ष करायी जा चुकी है।
- ग्राम समाज की कृषि भूमि 26,149 भूमिहीनों के मध्य 5513 हे0 भूमि वितरित ।
- आवास स्थल के लिए 53041 परिवारों के बीच 577 हे0 भूमि वितरित।
- मत्स्य पालन के लिए 17833 मछुआरों को 14417 हे0 तालाबों का आवंटन।
- कुम्हारी कला : 8772 कलाकारों को 6155 हे0 स्थल आवंटित किए गए।
- वृक्षारोपण के लिए 5564 लोगों को 31922 हे0 भूमि आवंटित।

प्रक्रिया का सरलीकरण

- **औद्योगीकरण** हेतु कृषि भूमि को गैर–कृषक भूमि घोषित कराने के लिए नियमों को शिथिल करते हुए 05 वर्ष के सम्भावित भू–उपयोग को देखते हुए कृषक से गैर–कृषक भूमि घोषित करने का प्रावधान किया गया है।

- 12.5 एकड़ से अधिक गैर कृषक भूमि क्रय करने हेतु शासन से अनुमति की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण कई वर्षों तक प्रकरण लम्बित पड़े रहते थे। इसका सरलीकरण करते हुए 50 एकड़ तक जिलाधिकारी, 100 एकड़ तक मण्डलायुक्त को शासन की शक्तियां प्रतिनिधानित कर दी गयी हैं। 100 एकड़ से अधिक भूमि क्रय करने हेतु पूर्व की भांति शासन के अनुमति की आवश्यकता होगी।
- प्रदेश में निजी भूमि को पट्टे पर देने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान की गयी है, जिससे कोई खातेदार कृषि कार्य के लिए 15 वर्ष तक अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकता है एवं सौर ऊर्जा के लिए 30 वर्ष हेतु भूमि पट्टे पर दे सकता है।
- **गाटों का यूनीक कोड :** समस्त गाटों को एक यूनिक कोड प्रदान करते हुए भूलेख पोर्टल (खतौनी) को निबंधन विभाग, राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली एवं भू–नक्शा पोर्टल से लिंक कर दिया गया है, जिससे कोई भी खातेदार कहीं से भी एक क्लिक पर भूमि के बन्धक, राजस्व न्यायालय में विवादित/वादग्रस्त होने या उसके बिक्रीत होने की प्रास्थिति को जान सकता है। इस कार्य से विवादित भूमि के क्रय–विक्रय और अनावश्यक वादों में भी बहुत कमी आयी है।
- राजस्व न्यायालयों के वादकारियों को वाद की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस द्वारा वाद सम्बन्धी सूचना भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त राजस्व वादों में पारित होने वाले निर्णय आर.सी.सी.एम.एस. से स्वतः जनित बारकोड युक्त आर्डर शीट पर ही लिखे जा रहे हैं और उन्हें तुरन्त वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाता है। इस व्यवस्था से राजस्व न्यायालयों की पारदर्शिता में बढ़ोत्तरी हुई है एवं वादकारियों को अनावश्यक उत्पीड़न से मुक्ति मिली है।

महिलाओं को समान अधिकार

- महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्व संहिता में पौत्री (पुत्र की पुत्री,) भतीजी (सगे भाई की पुत्री) और भांजियों (सगी बहन की पुत्री) को भी भौमिक अधिकार दिये जाने का प्राविधान राजस्व संहिता में किया गया है।
- अब पैमाइश के ऐसे प्रकरणों, जो अविवादित हों एवं सम्बन्धित पक्षकारों में पारस्परिक सहमति हो, के निस्तारण के लिए उपजिलाधिकारी के स्थान पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार को अधिकृत किये जाने का अन्तरिम निर्णय लिया गया है।

लेखपालों को स्मार्टफोन/लैपटॉप

- शासकीय कार्य की सुगमता हेतु समस्त लेखपालों/राजस्व निरीक्षकों को 28000 स्मार्ट फोन तथा 24,500 लेखपालों को लैपटाप उपलब्ध कराये गये हैं। समस्त राजस्व निरीक्षकों को लैपटाप देने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

प्रदेश सरकार ने आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा मेडिकल शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। सुगमता से दवाईयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गयी है। मरीजों को तत्काल राहत देने के लिए एम्बुलेंस सुविधा को भी सुदृढ़ किया गया है।

इंसेफेलाइटिस, काला ज्वार, मलेरिया समेत संक्रामक बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। प्रदेश के 38 जनपद जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित थे। विगत 40 वर्षों में इस संक्रामक बीमारी से 50 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें अधिकांश बच्चे थे। विगत ढाई वर्षों में प्रदेश सरकार के प्रयासों एवं अन्तर्विभागीय समन्वय से इस घातक रोग के मामलों में 35 फीसदी की कमी हुई है, जबकि मौत के आंकड़ों में 65 प्रतिशत की कमी आयी है।

- विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा एवं दस्तक अभियान के तहत घर–घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों की स्वास्थ्य इकाइयों को सुदृढ़ किया गया। इसी कारण ए.ई.एस. से होने वाली मृत्यु दर मात्र 3.73 प्रतिशत रह गई है, जबकि वर्ष 2016 में यह दर 16 प्रतिशत से अधिक थी।
- पूरे पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस के लिए टीकाकरण रिकॉर्ड समय में किया गया है। लगभग 40 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया है।
- बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में बेड की संख्या 268 से बढ़ाकर 428 की गई है, इसे आधुनिक वेंटिलेटर से जोड़ा गया है और साथ ही इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए वार्मर की भी संख्या बढ़ गई है। पीआईसीयू व मिनी पीआईसीयू को अपग्रेड किया गया है, वर्ष 2018 में 84 व वर्ष 2019 में 30 नए वेंटिलेटर बेड भी लगाए गए हैं।
- ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक 104 इंसेफेलाइटिस केंद्र (ई.टी.सी.) स्थापित।
- एई/जेई के विरुद्ध अभियान में 3.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया।
- इंसेफेलाइटिस उपचार केंद्र (ईटीसी) में रोगियों के लिए 24 घंटे उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी गयी, जिससे मृत्यु दर में और कमी आई है।
- जेई और एईएस की जाँच के लिए 19 जिलों के जिला अस्पतालों में 19 सेंटिनल लेबोरेटरी चालू करवाई गई।
- 15 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना की जा रही है, जिनमें से 07 मेडिकल कालेजों अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, बदांयू एवं शाहजहाँपुर और राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में मेडिकल शिक्षा एम.बी.बी.एस प्रथम वर्ष की पढ़ाई प्रारम्भ हो गई है।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना **"आयुष्मान भारत"** के अन्तर्गत 1 करोड़ 18 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रु. तक के चिकित्सा बीमा एवं 10 लाख 56 हजार वंचित परिवारों को **"मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना"** के जरिए लाभान्वित किया गया।
- 08 राजकीय मेडिकल कालेज एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर तथा मिर्जापुर का

निर्माण जारी है। इसके अलावा **14 राजकीय मेडिकल कालेज** खोलने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

- राज्य सरकार की फंडिंग से बदायूं और जौनपुर में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है।
- मेडिकल कालेजों में 1010 एम.बी.बी.एस. सीटों की बढ़ोतरी हुई है।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में "महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान", लहरतारा में होमीभाभा कैंसर हॉस्पिटल और बीआरडी मेडिकल कालेज गोखपुर में "सुपर स्पेशलिटी ब्लाक" कार्यशील हो चुके हैं।
- गोरखपुर एवं रायबरेली एम्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन दोनों एम्स में 50–50 एम.बी.बी.एस. सीटों पर छात्रों के एडमिशन का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न **अटल बिहारी वाजपेयी** की स्मृति में एक नये चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
- प्रदेश में पहली बार 250 नईं ए.एल.एस. (एडवांस लाईफ सपोर्ट) एम्बुलेंस संचालित की गईं।
- **712 नईं 108–एम्बुलेंस, 170 नईं एम.एम.यू.** (मेडिकल मोबाइल यूनिट्स) संचालित।
- 57 सी.एच.सी. के संचालन के साथ ही 4 नये सी.एच.सी. स्वीकृत। 52 पी.एच.सी. के संचालन के साथ 59 नये पी.एच.सी. स्वीकृत।
- टीकाकरण का कार्य 84 प्रतिशत पूर्ण।
- **वर्ष 2014 में मातृ–मृत्यु–दर 285 प्रति लाख के मुकाबले वर्ष 2019 में घटकर यह दर 201 प्रति लाख रह गई है। मातृ–मृत्यु–दर में सबसे ज्यादा 30 प्रतिशत गिरावट लाने के लिए उत्तर प्रदेश को भारत सरकार की ओर से एम.एम.आर. अवार्ड से नवाजा गया।**
- **वर्ष 2014 में शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हजार के मुकाबले वर्ष 2019 में 41 प्रति हजार रह गई।**
- औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता व लागत में कमी के लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन का गठन।

एईं/जेई से मृत्यु दर में कमी

एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिन्ड्रोम

वर्ष	मरीज़	मृत्यु
2016	3911	641
2017	4724	655
2018	3077	248
2019 (27 अगस्त तक)	1194	42

जापानी इंसेफेलाइटिस

वर्ष	मरीज	मृत्यु
2016	442	74
2017	693	93
2018	478	34
2019 (27 अगस्त तक)	89	4

शिक्षा की अलख

बेसिक शिक्षा

- **स्कूल चलो अभियान** के अन्तर्गत इस वर्ष 1.80 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया। 15000 प्राथमिक विद्यालयों तथा 1000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया।
- कक्षा 01 से 08 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म, स्कूल बैग, स्वेटर एवं जूता, ड्रेस, मोजा का वितरण कराया। इन्हें मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित किया गया।
- बालिकाओं को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा और राजकीय इण्टर कालेजों में सह शिक्षा की व्यवस्था।
- शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 25 विकास खण्डों में बालिका छात्रावास संचालित।
- 107 विकास खण्डों में बालिका छात्रावास का निर्माण प्रगति पर है।
- प्रदेश के स्कूलों में एन.सी.आर.टी. पाठ्यक्रम लागू किया गया। इन स्कूलों में मदरसे भी शामिल है।
- पहली बार मेधावी छात्र/छात्राओं को 1 लाख रुपये की धनराशि, टैबलेट, मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
- वर्ष 2018 में 45,383 अध्यापकों की प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की गयी।
- 69,000 अध्यापकों की प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती अन्तिम चरण में है।
- आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु एक नवीन कार्यक्रम **''शारदा–स्कूल हर दिन आयें''** प्रारम्भ। 80 हजार 836 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया।
- **''आपरेशन शिक्षा काया–कल्प''** के जरिए 91 हजार 236 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, बाउण्ड्री वॉल, गेट, शौचालय, पेयजल व विद्युतीकरण आदि कार्य कराये गये।

माध्यमिक शिक्षा

149 पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेजों का संचालन शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 4150 पदों का सृजन।

- राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गयी।
- मान्यताप्राप्त वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अध्यापकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार देने का निर्णय।
- **बेटी पढ़ाओ–बेटी बचाओ योजना** के तहत 100 टापर छात्राओं, 100 टापर एससी/एसटी छात्र–छात्राओं तथा डिप्लोमा सेक्टर की प्रवेश परीक्षा में प्रवेश लेने वाले 300 टापर छात्र–छात्राओं को लैपटाप दिया गया।
- निजी विद्यालयों में ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए उ0प्र0 स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 लागू।
- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की **नकलविहीन परीक्षाएं** हुईं।
- 7 नवीन राजकीय इण्टर कालेज एवं 1

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण किया गया।

- 193 नए इण्टर कालेज शुरू किए गए। 55 नए इण्टर कालेजों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा

- 51 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
- उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए 07वें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू।
- 14 राज्य विश्वविद्यालयों में पं0 दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना।
- पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना।
- पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना।
- जनपद सहारनपुर एवं आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि एवं बजट की व्यवस्था।

प्राविधिक शिक्षा

- 24 राजकीय पॉलीटेक्निक एवं 28 छात्रावास निर्मित।
- 22 नये राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना की प्रक्रिया प्रारम्भ।
- प्रतापगढ़, बस्ती, गोण्डा एवं मीरजापुर में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- पॉलीटेक्निक शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़कर 1325 हो गई। इन शिक्षण संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़कर 230275 हो गई।

कौशल विकास, स्टार्ट–अप को महत्व

स्टार्ट–अप, स्टैण्ड अप संस्कृति को बढ़ावा

- प्रदेश में स्टार्ट–अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 13 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड–अप इण्डिया योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 18,490 रोजगार का सृजन।
- **कौशल से मिला रोजगार**
- समन्वित कौशल विकास नीति प्रख्यापित करने वाला देश में प्रथम राज्य।
- प्रदेश की सभी असेवित तहसीलों में 79 में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा 59 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र खोले गए।
- कौशल प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण से लेकर उनके प्रशिक्षण समाप्ति व सेवायोजन की पूर्णतः पारदर्शी एवं ऑनलाइन प्रक्रिया।
- वर्ष 2018–19 तक 10 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण, 8.48 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित तथा 3 लाख से अधिक युवा सेवायोजित।
- एसौचैम द्वारा कौशल विकास में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्वर्ण ट्राफी।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु बैंको के माध्यम से रू0 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10.00 लाख तक के ऋण की व्यवस्था।

घर-घर बिजली

विकास के लिए बिजली अपरिहार्य है। पिछली दो सरकारों के 10 साल के कार्यकाल में बिजली सिर्फ प्रदेश के 5 वी.आई.पी. जिलों तक ही सीमित थी, लेकिन अब बिना किसी भेदभाव के सभी को बिजली मुहैया करायी जा रही हैं। जनपद मुख्यालयों में 22 से 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। सौभाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने पर भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया है। वर्तमान सरकार के कुशल प्रबन्धन के कारण तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में भी बेहद कमी आयी है। वर्ष 2013-14 में 38.29 प्रतिशत के मुकाबले 2018-19 में यह हानियां 24.64 प्रतिशत रह गयी हैं।

- प्रदेश के सभी परिवारों को विद्युत सुलभ कराने के लिए **''पावर फार आल''** योजना संचालित।
- 2 करोड़ 91 लाख 76 हजार घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किये गये।
- अब तक शत–प्रतिशत 1 लाख 78 हजार 168 मजरों का विद्युतीकरण।
- **सौभाग्य योजना** के तहत विद्युत कनेक्शन जारी करने में उत्तर प्रदेश देश में **शीर्ष स्थान** पर है। **1 करोड़ 9 लाख** से अधिक घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया।
- 613 नये विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के साथ ही 761 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है।
- वर्ष 2014 में विद्युत उत्पादन क्षमता जहां 10442 मेगावाट थी, वहीं वर्ष 2019 में बढ़कर 20921 मेगावाट हो गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर 48 घंटे के अंदर मरम्मत/नये ट्रांसफॉर्मर की स्थापना की जा रही है।
- 2 करोड़ 58 लाख से अधिक स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी का वितरण किया गया। इससे सलाना 3469 मिलियन किलोवाट बिजली की बचत संभावित है।
- उपभोक्ताओं को घर बैठे कनेक्शन लेने के लिए **ई–संयोजन मोबाइल एप लांच**।
- बुंदेलखंड के किसानों को बिजली बिल के फिक्स चार्ज में 50 से 75 प्रतिशत की छूट।
- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में वृद्धि के लिए **"नई सौर ऊर्जा नीति"** लागू करते हुए सौर ऊर्जा सेक्टर में 1535 मेगावाट के 7500 करोड़ रु. के प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने पर शत–प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट।
- इस नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10700 मेगावाट क्षमता सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित।
- वर्ष 2014 में 12 मेगावाट सौर उत्पादन की तुलना में वर्ष 2019 में बढ़कर 894 मेगावाट उत्पादन क्षमता हुई।
- **पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना** के अन्तर्गत ग्रामीण बाजारों में 23050 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना।
- **मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना** में चयनित राजस्व ग्रामों में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हेतु **7120 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों** की स्थापना।।
- सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था हेतु **22000 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों** की स्थापना।
- कृषि विभाग के सहयोग सें **12656 सोलर पम्प** सिंचाई की स्थापना।
- प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं पंखें की व्यवस्था हेतु **1980 सोलर आर0ओ0 वाटर प्लान्ट्स** की स्थापना।

इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार

प्रदेश में राजमार्गों, सड़कों और पुलों के निर्माण को प्राथमिकता दी गयी है। आधारभूत संरचना मजबूत करने की दृष्टि से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जा चुकी है। एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए कुल 3194 करोड़ रुपये की व्यवस्था। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हेतु 1194 करोड़ रुपये, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे हेतु 1-1 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- 341 किमी. लम्बे पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अगस्त 2020 तक इसे संचालित कर दिया जाएगा।
- 92 कि.मी. लम्बे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के लिए प्रक्रिया प्रगति पर।
- 297 कि.मी. लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के लिए निविदाएं आमंत्रित। डिफेन्स कॉरिडोर विकसित किये जाने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारम्भ।
- मेरठ से प्रयागराज तक 640 कि0मी0 लम्बे 'गंगा एक्सप्रेस–वे' के निर्माण का निर्णय।
- आगरा–लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन

एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- 129441 किमी0 सड़कें गड्ढामुक्त।
- 66700 कि0मी0 लम्बे मार्ग का नवीनीकरण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 7948 कि0मी0 सड़कों का निर्माण पूर्ण।
- 115 दीर्घ सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर। 79 दीर्घ सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण।
- 86 रेल उपरिगामी का निर्माण कार्य प्रगति पर। 27 रेल उपरिगामी सेतुओं का अप्रोच मार्ग पूर्ण।
- वर्तमान में 304 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर, जिसमें से 107 लघु सेतुओं का अप्रोच मार्ग पूर्ण।
- लगभग 10,134 कि.मी. लम्बाई में मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।
- कुम्भ–2019 के दौरान प्रयागराज में रू0 1578.88 करोड़ की लागत से लगभग 646 कि.मी. सड़क का निर्माण किया गया।
- 26 तहसील मुख्यालयों को 2 लेन मार्ग जोड़ने का कार्य प्रगति पर।
- 152 विकास खण्ड 2 लेन मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रारम्भ किया गया।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** में 4136 किमी. से अधिक सड़कें निर्मित।
- 250 से अधिक आबादी के असम्बद्ध गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु रु. 1,114 करोड़ स्वीकृत। समस्त बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु रु. 1333 करोड़ से कार्य प्रारम्भ।
- प्रदेश के 14,561 असेवित गांवों को बस सेवा से जोड़ा गया।
- प्रदेश में 9722 किमी0 लम्बाई के मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण।
- 716 मार्गों की 04 लेन सड़कों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर।
- मेधावी छात्रों के निवास स्थलों तक 113 सड़कों का निर्माण/मरम्मत कर **''डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरव पथ''** के रूप में विकसित किया गया।
- पारदर्शिता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग के बजट, पंजीकरण, ई–एमबी, ई–बिलिंग, ई–डिमांड, ई–एलॉटमेंट को ऑनलाइन करने के लिए **''चाणक्य'' एवं ''विश्वकर्मा''** नाम से दो बड़े साफ्टवेयर लागू।
- प्रदेश की समस्त सड़कों पर जनता की नजर रखने के लिए **''निगरानी एप''** का निर्माण किया गया।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अंतर्गत प्रदेश में 1688.27 किमी0 की सड़कों का निर्माण किया गया।
- प्रथम बार नई तकनीक (वेस्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, नैनों टेक्नोलॉजी, फ्लाई ऐश, सीसी ब्लाक आदि) आदि का प्रयोग कर 1682 किमी. सड़क का निर्माण किया गया।

वायु सेवाएं

- प्रदेश में 08 हवाई अड्डे क्रियाशील। इनसे 55 स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। 11 नये एयरपोर्ट का निर्माण प्रगति पर।

- 1334 हे0 में नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। प्रथम चरण का निर्माण कार्य वर्ष 2022 तक पूर्ण होना संभावित है। एयरपोर्ट का संचालन वर्ष 2023 से होना संभवित है।

मेट्रो सेवाएं

- **लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना** के तहत 23 कि.मी. कॉरीडोर (अमौसी से मुन्शी पुलिया) संचालन प्रारम्भ।
- कानपुर, झाँसी, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ शहरों के लिए मेट्रो या रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना तैयार।
- **कानपुर मेट्रो रेल परियोजना** के तहत 11076 करोड़ की लागत से 5 वर्षों में 32.4 कि.मी. लम्बे 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।

परिवहन सुविधाएं

- **निर्भया फण्ड योजना**– के तहत महिला यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी बसों में पैनिक बटन एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा की व्यवस्था करने वाला **उत्तर प्रदेश पहला राज्य**।
- 19494 असेवित गांवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **'संकल्प बस सेवा'** का संचालन किया गया।
- पड़ोसी राज्य नेपाल हेतु अयोध्या से जनकपुर, **लखनऊ–रूपईडीहा–नेपालगंज, दिल्ली से महेन्द्र नगर, पोखरा व नेपालगंज** के लिए अन्तर्राज्यीय बस सेवा संचालित।
- मैन्युअल चालान व्यवस्था समाप्त कर ई–पेमेंट से जुर्माना भुगतान की सुविधा हेतु ई–चालान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश देश का **पहला राज्य** बना।
- **रक्षाबंधन पर्व – वर्ष 2019 में 12.03 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा प्रदान की गयी।**

औद्योगिक विकास का नया सवेरा

योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण के बाद औद्योगिक विकास क्षेत्र में एक नया सवेरा आया। मात्र ढाई साल के कार्यकाल में इन्वेस्टर्स समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-1, प्रवासी भारतीय दिवस और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-2 का आयोजन हुआ और कुल 2 लाख करोड़ रु. के निवेश को सुनिश्चित किया गया, जो प्रदेश के औद्योगिक विकास के इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके साथ ही डिफेन्स इण्डस्ट्रियल मैन्यूफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना में भी 20 हजार करोड़ रु. के निवेश का रास्ता खुला है।

- नई औद्योगिक नीति लागू। प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर। निवेश फ्रेण्डली 21 नई नीतियां बनाई गयी।
- लखनऊ में फरवरी, 2018 में उत्तर प्रदेश **इन्वेस्टर्स समिट** का आयोजन किया गया।
- समिट में **4.68 लाख करोड़** रुपये के निवेश सम्बन्धी एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित।
- **प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी** एवं **द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी** तथा आयोजनों के माध्यम से लगभग **2 लाख करोड़ रुपये** के निवेश की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी। इन परियोजनाओं से लगभग **5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।**
- प्रधानमंत्री जी द्वारा बुन्देलखण्ड में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल मैन्यूफैक्चरिंग कॉरीडोर का शिलान्यास किया गया। 20 हजार करोड़ रु. के निवेश से बनने वाले इस कॉरिडोर के जरिए 2.5 लाख लोगों का रोजगार सृजन होगा।
- **निवेश मित्र पोर्टल** के माध्यम से उद्यमियों के 46220 आवेदनों को निस्तारित किया गया।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** के तहत बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लॉन लागू। इससे प्रदेश 92.87 प्रतिशत स्कोर के साथ अग्रणी राज्यों में शामिल।
- **एक जनपद–एक उत्पाद समिट–2018 (ओ.डी.ओ.पी.) का आयोजन कर 1 लाख 91 हजार 191 लाभार्थियों को लगभग 18 हजार 345 करोड़ रुपये का ऋण वितरित। ओ.डी.ओ.पी. से लगभग 5 लाख हुनरमंदों को रोजगार मिलेगा।**
- प्रदेश से **1 लाख 14 हजार करोड़ रु.** से अधिक का निर्यात किया गया, जो विगत वर्षो से **25 हजार करोड़ रु. अधिक** है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या में **उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।**
- प्रदेश में पहली बार 21 से 23 जनवरी, 2019 को वाराणसी में 15वें **प्रवासी भारतीय दिवस** का आयोजन, जिसमें देश–विदेश से दिग्गज अप्रवासी भारतीय सम्मिलित हुए।

नगर : स्वच्छता के लिए सम्मान

प्रदेश के 14 निकायों को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सम्मानित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष-2019 में राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर हैं।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देश में **प्रथम** स्थान पर है।
- योजनान्तर्गत स्वीकृत 12 लाख 97 हजार 212 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 2 लाख 52 हजार निर्मित किए जा चुके हैं, जबकि वर्ष 2014 से 2017 तक मात्र 10262 आवास ही स्वीकृत किए गए थे।
- सभी 75 जनपद खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित।
- 8 लाख 33 हजार व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्मित। 652 नगर निकाय ओपन डेफीकेशन मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित।
- नगरों में 4 हजार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया।

स्मार्ट सिटी

- **स्मार्ट सिटी योजना** के तहत चयनित प्रदेश के 10 शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ में 20 हजार करोड़ की परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

अमृत योजना (AMRUT)

- **अटल नवीकरण एवं शहरी रुपान्तरण मिशन (अमृत, AMRUT) योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के 60 शहर आच्छादित।

नमामि गंगे

- **नमामि गंगे परियोजना** के तहत 45 सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत करते हुए 12 पूर्ण, शेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर।

संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों की रोजी-रोटी की सुरक्षा, उनकी आय बढ़ाने, उनकी स्वास्थ्य सुविधा और उनके मान-सम्मान पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। इससे श्रमिकों के चेहरे पर चमक आनी शुरु हो गयी है।

श्रमिकों के अच्छे दिन

- प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों **बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई** आदि स्वरोजगारियों तथा पारम्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन एवं सम्वर्धन तथा उनकी आय में वृद्धि हेतु **'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना'** का शुभारम्भ एवं **'उ0प्र0 माटी कला बोर्ड'** का गठन किया गया।
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके **श्रमिकों को प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन सहायता योजना संचालित की गयी।** योजना के अन्तर्गत 49,41,825 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया गया।
- कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी विकलांगता पर 03 लाख रुपये एवं आंशिक विकलांगता पर 02 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है।
- असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए **'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान–धन योजना'** उत्तर प्रदेश में लागू कर 5,13,917 श्रमिकों को पंजीकृत किया गया।

- बाल श्रम उन्मूलन हेतु **नया सवेरा योजना** के तहत 18,376 बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ा गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में 7474 लाभार्थियों को प्रशिक्षित कर टूल किट उपलब्ध कराए गये।

समाज कल्याण

सम्मानजनक जीवन के रास्ते खुले

समाज के सभी वर्गों को सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए प्रदेश सरकार हर सम्भव मदद कर रही है। इसी क्रम में 40 लाख 71 हजार से अधिक वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, 21 लाख 69 हजार से अधिक निराश्रित महिलाओं को निराश्रित पेंशन, 9 लाख 84 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन राशि 400 रु. से बढ़ाकर 500 रु. तथा दिव्यांग पेंशन राशि 300 रु. से बढ़ाकर 500 रु. प्रतिमाह की गयी।

- **"मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना"** के अन्तर्गत सभी वर्गों के निर्धन परिवारों की 68108 गरीब कन्याओं की शादी करायी गयी है। इस योजना के तहत 35 हजार रु. की धनराशि बढ़ाकर अब 51000 रु. कर दी गयी है।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र–छात्राओं को पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 8 लाख 90 हजार और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कुल 24 लाख 53 हजार छात्र–छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान की गई है।
- सामान्य वर्ग के छात्र–छात्राओं को भी विगत दो वर्षों में दशमोत्तर एवं पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 19 लाख से अधिक छात्र–छात्राओं को लभान्वित कराया गया।
- ओ.बी.सी. छात्र–छात्राओं को पूर्वदशम छावृत्ति योजना के तहत 18.83 लाख से अधिक तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत लगभग 37 लाख छात्र– छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं को चालू

वित्तीय वर्ष में 17,500.00 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान।

- पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ–लेवल सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 1500 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2019–20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 74,097.00 लाख रुपये एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 60,000.00 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत इस वर्ष अब तक 21,895 परिवार लाभान्वित।
- श्रमिकों के बच्चों के लिए सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाने की योजना।
- अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की गयी।
- **94 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम** पद्धति विद्यालय संचालित।
- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम** के तहत 42 राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण पूर्ण।

पेंशन योजना व अन्य सहायता

- **वृद्धावस्था पेंशन** 400 से बढ़ाकर 500 रु. प्रति माह की गई। 41,57,308 पात्र वृद्धजनों को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।
- विधवा पेंशन हेतु आयु सीमा की बाध्यता समाप्त की गयी।
- वर्ष 2016–17 में निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 17.32 लाख थी, जो 2018–19 में बढ़ाकर 21.69 लाख पहुँच गयी।
- **दिव्यांगजन पेंशन** रु. 300 से बढ़ाकर रु. 500 प्रतिमाह की गयी।
- वर्ष 2017 में दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 883157 थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 984709 पहुंच गई।
- दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जनपद लखनऊ को सर्वश्रेष्ठ जनपद का पुरस्कार दिया गया।
- अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 25 नए कोर्ट गठित करने का निर्णय।
- 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- **छात्रवृत्ति रु.2250 से बढ़ाकर रु. 3000 की गयी। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इसके लिए रु. 2067 करोड़ का प्रावधान किया गया।**
- एससी, एसटी व पीसीआर एक्ट के तहत 15,472 परिवारों को रु. 155 करोड़ की सहायता।
- अल्पसंख्यक महिलाओं को बिना महरम हज पर जाने की सुविधा प्रदान की गयी।
- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत कुल 1736 करोड़ की परियोजनायें स्वीकृत।
- अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान हेतु रु. 20000 की सहायता। पिछले वर्ष की अपेक्षा 62 प्रतिशत अधिक पुत्रियाँ लाभान्वित।

सौजन्य से- उत्तर प्रदेश सरकार

पशुओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

गोवंश संरक्षण

छुट्टा गोवंश के भरण-पोषण एवं आश्रय की समुचित व्यवस्था हेतु बन्देलखण्ड के 7 जनपदों में 36 पशु आश्रय गृहों के निर्माण तथा 16 नगर निगमों में छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु गोशालाओं के लिए धनराशि जारी की गई। 4301 गोवंश आश्रय स्थल तथा 2.97 हजार संरक्षित गोवंश आश्रय स्थल संचालित किए गए।

मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत कृषकों/ पशुपालकों को रु. 30 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से निराश्रित गांवश के भरण-पोषण के लिए रु. 80 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- सभी जनपदों में 2–2 वृहद गोवंश संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु 180 करोड़ रू0 की स्वीकृति दी गयी।
- सभी जनपदों में छुट्टा गोवंश के भरण–पोषण के लिए रू0 158.50 करोड़ की स्वीकृति दी गयी।
- बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों में 36 पशु आश्रय गृहों के निर्माण हेतु 10.32 करोड़ रू0 की स्वीकृति दी गयी।
- प्रदेश की 39 पंजीकृत गोशालाओं के गोवंश के भरण–पोषण के लिए मण्डी परिषद द्वारा 22.62 करोड़ रू0 की धनराशि जारी की गयी।
- 16 नगर निगमों में छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु गोशालाओं को रू0 17.52 करोड़ दिये गये।
- गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण हेतु 75.25 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी।
- अबतक 539.88 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया।
- 31.16 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया।
- 113.24 लाख पशुओं का उपचार किया गया।

- 4.95 लाख कि0ग्रा0 ऊन उत्पादन किया गया।

दुग्ध उत्पादन व अन्य

- वर्ष 2017 में प्रदेश में 277.69 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन होता था। इसे वर्ष 2018–19 में बढ़ाकर 304.94 लाख मीट्रिक टन किया गया। दुग्ध उत्पादन में देश में **उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान** पर है।
- **दुग्ध उत्पादन में प्रतिदिन 50 लाख कि.ग्रा. की वृद्धि हुई है।**
- **10 ग्रीनफील्ड नवीन डेयरी प्लान्ट्स की स्थापना एवं 4 डेयरी प्लान्ट्स का नवीनीकरण/उच्चीकरण किया गया है।**
- 2017–18 में अंडा उत्पादन 24398 लाख था, जो 2018–19 में बढ़कर 26050 लाख हो गया।
- कुक्कुट इकाइयों से 98.82 लाख अण्डों का अतिरिक्त उत्पादन और 53920 लोगों को रोजगार।

मत्स्य पालन

- मत्स्य जलाशयों हेतु न्यूनतम ठेका अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की गई।
- मत्स्य पालकों को 28,868 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीजों का वितरण।
- **कम जल तथा कम भूमि में अधिक मत्स्य उत्पाद की नई तकनीक के अन्तर्गत 25 री–सरकुलेट्री एक्वाकल्चर सिस्टम स्थापित कराये गये।**
- **प्रदेश में इस वर्ष 6.62 लाख टन मत्स्य उत्पादन हुआ है।**
- मत्स्य पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा अनुमन्य की गई है।
- **नीली क्रान्ति हेतु ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट फॉर फिशरीज** (केन्द्र पोषित) कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।
- निःशुल्क मछुआ दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है।
- 138 फिश सीड रियरिंग यूनिट्स की स्थापना की गयी है।
- 270 लाभार्थियों को तालाब सुधार हेतु अनुदान दिया गया है।
- 448 मछुआ आवासों के सापेक्ष 353 मछुआ आवास निर्माणाधीन तथा 95 आवास के निर्माण हेतु प्रथम किस्त निर्गत की गई।
- 13,4014 मछुआरों को **प्रधानमंत्री सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना** के दायरे में लाया गया।
- 5454 हे0 जलक्षेत्र के ग्राम सभा तालाबों का पट्टा आवंटन कराते हुए मत्स्य पालन हेतु 5606 परिवारों को आच्छादित किया गया।
- वर्ष 2018–19 में मत्स्य पालकों को 29442 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज उपलब्ध कराया गया।
- 688 मत्स्य नर्सरियों का निर्माण कराया गया।

पर्यटन एवं संस्कृति में ऊँचे आयाम

- उत्कृष्ट ब्रांडिंग से वर्ष 2018 में कुल 2888.60 लाख पर्यटकों ने प्रदेश का भ्रमण किया, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 2850.80 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 37.80 लाख है।
- मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विन्ध्यांचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर, गोरखपुर और वाराणसी आदि नगरों में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
- अयोध्या में दीपावली के पर्व पर सरयू तट पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।
- वर्ष 2018 में छोटी दीपावली के दिन 3,31,052 दिये जलाकर **गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड** बनाया गया।
- दीपोत्सव में 5 देशों की रामलीलाओं के साथ तीन दिन तक अयोध्या, चित्रकूट और लखनऊ में रामलीलाओं का मंचन किया गया। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक द्वारा श्रीराम सीता जी व लक्ष्मण जी की बालू की कलाकृति का निर्माण किया गया।
- चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत पर श्रद्धालुओं/पर्यटकों की सुविधा के लिए रोप–वे का लोकार्पण किया गया।
- **काशी विश्वनाथ कॉरिडोर** के विकास के लिए तेज़ी से कार्य किया जा रहा है।
- वाराणसी के प्रसिद्ध मन्दिरों पर आधारित पावन पथ **'वाराणसी वेबसाइट'** का निर्माण किया गया।
- **स्वदेश दर्शन योजना** के अन्तर्गत रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, हेरिटेज सर्किट एवं स्प्रिचुएल सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, महाभारत सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट एवं जैन सर्किट का चिह्नांकन कर समेकित पर्यटन विकास कार्य किया जा रहा है।
- स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत रु. 133 करोड़ की लागत से अयोध्या का समेकित पर्यटन विकास किया जा रहा है।
- रामायण सर्किट के अन्तर्गत रु. 69.45 करोड़ से चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर का पर्यटन विकास किया जा रहा है।
- बुद्धिस्ट सर्किट के अन्तर्गत रु. 99.97 करोड़ की लागत से श्रावस्ती एवं कुशीनगर का पर्यटन विकास किया जा रहा है।
- वाराणसी में गंगा नदी में अस्सी घाट से राजघाट के मध्य रिवर क्रूज संचालित किया जा रहा है।
- रु0 44.60 करोड़ से वाराणसी में पर्यटन विकास किया जा रहा है।
- रु0 39.73 करोड़ से गोवर्धन (मथुरा) का पर्यटन विकास किया जा रहा है।
- गोरखपुर–देवीपाटन–जेवर–खुर्जा का स्पिरीचुअल सर्किट के अन्तर्गत पर्यटन विकास किया जा रहा है।
- **ईको–टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग एवं वन विभाग द्वारा–दुधवा टाईगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाईगर रिजर्व स्थलों का पर्यटन विकास किया जा रहा है।**

- **प्रदेश के विभिन्न प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर–राइड की सुविधा सुलभ कराने की कार्यवाही प्रगति पर है।** वाराणसी, मथुरा, आगरा, प्रयागराज एवं लखनऊ में हेलीपोर्ट/ हेलीपैड/ एअर स्ट्रिप के निर्माण का कार्य प्रगति पर।
- प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से घरेलू पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है।
- उ0प्र0 की ब्राण्डिंग के लिए **''यूपी नहीं देखा तो इण्डिया नहीं देखा''** तथा कुम्भ के लिए **''सर्वसिद्धिप्रदः कुम्भः''** टैग लाइन जारी की गई।
- कुम्भ क्षेत्र में **"संस्कृति ग्राम"** एवं **"कला कुम्भ"** की स्थापना की गई।
- कुम्भ मेला, प्रयागराज–2019 में 05 मंचों पर निरन्तर 40 दिनों तक लोक, शास्त्रीय एवं नाट्य आदि विधाओं के 12500 कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। प्रयागराज में 45 दिनों तक एवं 25 अन्य स्थानों पर भी स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं।
- कुम्भ मेला प्रयागराज–2019 के अन्तर्गत 11 देशों की रामलीला, कृष्णलीला एवं रामायण गान की प्रस्तुतियां दी गईं।
- बरसाना में रंगोत्सव के भव्य आयोजन की परम्परा प्रारम्भ की गई। रंगोत्सव में 8 राज्यों के 1500 कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी गईं।
- मथुरा में श्रीकृष्णोत्सव में 900 कलाकारों के साथ मुम्बई के प्रसिद्ध दही–हाण्डी कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।
- प्रदेश की रामलीलाओं का तीन कैरेबियन देशों– त्रिनिडाड, गुयाना एवं सूरीनाम तथा मॉरीशस में मंचन कराया गया। साथ ही विदेश में रामलीलाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया।
- अयोध्या में प्रतिदिन मंचित की जाने वाली जिस रामलीला को बंद कर दिया गया था, उसे पुनः प्रारम्भ कराया गया। अयोध्या शोध संस्थान के अत्याधुनिक प्रेक्षागृह की मरम्मत हेतु रु. 450.00 लाख तथा **'राम की सांस्कृतिक विश्व यात्रा'** हेतु रु. 30.00 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया।
- **'राम की सांस्कृतिक विश्व यात्रा'** और **'रामलीला अकादमी'** की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।
- देव–दीपावली, उत्तर प्रदेश दिवस, माननीय प्रधानमंत्री जी, विदेश के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा अन्य गणमान्य अतिथियों के आगमन पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- थारू जनजाति पर आधारित विशेष संग्रहालय की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।
- **संत कबीर अकादमी की स्थापना की गई।**
- स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति की स्थापना एवं भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेई, महन्त दिग्विजय नाथ, महन्त अवैद्यनाथ की प्रतिमा निर्माण का कार्य प्रगति पर।
- प्रदेश के चित्रकारों का पहली बार विदेश (बैंकाक) में रचनाकार शिविर आयोजित ।
- **गोरखपुर में 5000 की दर्शक क्षमता के प्रेक्षागृह एवं खुले मंच की स्थापना।**

Committed To Your Success....

सौजन्य से- उत्तर प्रदेश सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तथा स्टार्ट-अप नीतियां लागू की गयीं। गोरखपुर सहित 7 नगरों में आई.टी. पार्क्स का निर्माण कार्य आगे बढ़ा। आई.टी सिटी लखनऊ में 400 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। स्टार्ट-अप को बढ़ावा मिला। इससे 1400 से अधिक ईकाइयां क्रियाशील हुई हैं।

आम आदमी से जुड़े 78193 से अधिक जन सेवा केन्द्र स्थापित हुए, जिनमें से 53984 को जियो टैग किया गया और उनको ''शनल सेन्टर ऑफ जियो इन्फारमेटिक्स पोर्ट'' पर भी ऑन-बोर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश में 7.32 लाख डिजिटल लाकर खोले गए।

- प्रदेश सरकार के 117 विभागों/कार्यालयों में "मानव सम्पदा पोर्टल" का क्रियान्वयन कर 936637 अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा–पुस्तिकाओं से सम्बन्धित विवरण अपलोड किया गया।
- नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया।
- 150 करोड़ रुपये के निवेश एवं करीब 15 हजार रोजगार की संभावनाओं से युक्त मेरठ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है।
- इन्वेस्टर्स समिट में इलेक्ट्रानिक तथा आईटी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश के एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। इनके क्रियान्वयन के बाद 150000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
- चीन, ताइवान, कोरिया देश की इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्षेत्र की विदेशी कम्पनियों ने प्रदेश में निवेश के प्रति रुचि प्रदर्शित की है।

- कुम्भ में 7 हजार से अधिक लोगों ने पेंटिंगवाल पर हाथों की छाप से हस्तलिपि चित्रकारी का विश्व रिकार्ड बनाया। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ।
- प्रयागराज कुम्भ–2019 में 503 शटल बसों का एक साथ एक रूट पर सफल संचालन करने के साथ ही गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज हुआ।
- सेनिटेशन के लिए कुम्भ मेले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया।
- 22 हजार स्वच्छताग्रहियों ने कुम्भ को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया।
- आस्था विश्वास और श्रद्धा से सराबोर कुम्भ मेले को यूनेस्को ने 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर' के रूप में मान्यता दी।
- कुम्भ–2019 में पहली बार 72 देशों के राजदूतों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों में से 187 देशों के प्रतिनिधियों ने दिव्य एवं भव्य कुम्भ के वैभव का अवलोकन किया।
- कुम्भ–2019 में 1,22,500 से अधिक इकोफ्रेन्डली शौचालयों का रिकार्ड निर्माण किया गया।
- कुम्भ–2019 में सफाई कार्य में अप्रतिम योगदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सफाईकर्मियों के पांव पखार कर सम्मानित किया गया।
- कैलाश मानसरोवार यात्रियों की अनुदान राशि 50 हजार रु. से बढ़ाकर 1 लाख रु. प्रति यात्री की गयी।
- सिंधु दर्शन का अनुदान 20 हजार रु. प्रति यात्री की गयी।

वन एवं पर्यावरण

प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण महाकुम्भ के अन्तर्गत 22 करोड़ से अधिक वृक्षों को रोपण किया गया। प्रयागराज में एक निश्चित समयावधि में एक ही स्थान पर 76 हजार 824 पौध वितरण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए ''गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड'' में दर्ज किया गया।

- गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किये जाने वाले वृक्षारोपण के अन्तर्गत वर्ष 2017 में 5.70 करोड़ पौधों, वर्ष 2018 में 11.12 करोड़ पौधों तथा वर्ष 2019 में 22.59 करोड़ पौधों का रोपण किया गया।
- **गंगा हरीतिमा अभियान संचालित।** गंगा नदी के किनारे स्थित बिजनौर से बलिया तक प्रदेश के 27 जिलों में अभियान चला कर दोनों किनारों से एक किमी0 दूरी के क्षेत्र में 09 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण से प्रदेश के वनाच्छादन क्षेत्र में वृद्धि।
- **मानव वन्यजीव संघर्ष** को आपदा घोषित करने वाला, उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य।
- पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पॉलीथिन के निर्माण एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जनपद प्रयागराज में भारत छोड़ो आन्दोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर वृक्षारोपण महाकुम्भ कार्यक्रम में 76823 निःशुल्क पौध वितरण के लिए प्राप्त गिनीज विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र के साथ।

महिला सशक्तिकरण

कन्याओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण बदलने के लिए 'कन्या सुमंगला योजना' लागू की गयी है, ताकि कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति पर नियंत्रण हो सके, स्वस्थ लैंगिक अनुपात तथा बलिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सम्मान को प्रोत्साहन मिले एवं बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो सके।

नारी सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 20 नवम्बर, 2018 से 18 दिसम्बर, 2018 तक 'नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान' चलाया गया। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में निराश्रित महिला पेंशन योजना, कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश में वन स्टॉप सेन्टर, जनसम्पर्क अभियान, नारी शक्ति शिविर, नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान, स्वावलम्बन सम्मेलन कार्यक्रम, बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना तथा बाल संरक्षण सेवा आदि शामिल हैं।

- **पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुल 1936714 लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 2168795 लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया। इस प्रकार निराश्रित महिला पेंशन योजना में 232081 लाभार्थियों की वृद्धि हुई है।**
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गरीब महिलाओं को 01 करोड़ 35 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।**
- **वृंदावन में निराश्रित महिलाओं के लिए 01 हजार बेड का आश्रय सदन बनाया गया।**
- **181 महिला हेल्प लाइन** व **रेस्क्यू वैन** की सेवा प्रदेश के सभी जिलों में संचालित।
- कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा **'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना'** लागू।
- **प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना** के तहत अब तक 18,57,038 लाभार्थी हुए लाभान्वित।
- सितम्बर 2019 में धात्री माताओं एवं शिशुओं के लिए पोषण माह कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

खेलोगे तो बढ़ोगे

राज्य के प्रतिभा सम्पन्न खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में प्रदेश सरकार कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों को विश्व के सबसे बड़े ओलम्पिक गेम्स में भाग लेने के लिए प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव सहूलियत मुहैया करा रही है। इस संकल्पना को मूर्तरूप देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (इकाना स्टेडियम) लखनऊ में भारत बनाम वेस्टइंडीज के मध्य टी-20 मैच का सफलतापूर्वक आयोजन कराया गया।

- **पद्मश्री मो0 शाहिद सिन्थेटिक हॉकी स्टेडियम,** लखनऊ तथा गोरखपुर में प्रथम बार भारत और फ्रांस के मध्य महिला हॉकी टेस्ट सीरीज का भव्य आयोजन कराया गया।
- **बाबू बनारसी दास इण्डोर स्टेडियम** में प्रो–कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया।
- भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (इकाना स्टेडियम) लखनऊ में भारत बनाम वेस्टइंडीज के मध्य टी–20 मैच का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हेतु पारदर्शी चयन व्यवस्था। 16 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।
- **रियो ओलम्पिक गेम्स** में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली **सुश्री पी0वी0 सिंन्धु, सुश्री साक्षी मलिक, सुश्री दीपा करमाकर** को **01–01 करोड़ रुपये** का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 12वें साउथ एशियन गेम्स–2016 में **स्वर्ण पदक** प्राप्त करने वाले उ0प्र0 के वुशू एवं हैण्डबाल खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।
- आई0सी0सी0 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप–2017 लन्दन में **रजत पदक प्राप्त** करने वाली भारतीय टीम की

प्रतिभागी उ0प्र0 की 02 महिला खिलाड़ियों **सुश्री दीप्ति शर्मा** एवं **पूनम यादव** को **रू0 8–8 लाख** की नकद धनराशि से सम्मानित किया गया।

- प्रत्येक जनपद में 02–02 जनपद स्तरीय प्रतियोगिता, प्रत्येक मण्डल स्तर पर 01–01 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता तथा कुल 168 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- प्रथम बार 24 जनवरी को उ0प्र0 दिवस के अवसर पर कबड्डी, कुश्ती एवं हॉकी खेल के महिला/पुरूष वर्ग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- प्रथम बार **''खूब खेलो– खूब पढ़ो''** पखवाड़े (1 से 15 फरवरी,2019 तक) के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिलें में 02–02 तथा मण्डल स्तर पर 04–04 जिला स्तरीय कुल 186 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हेतु प्रदेशीय टीमों को उच्च गुणवत्ता के खेल किट हेतु किट की धनराशि रू0 1000 से बढ़ाकर रू0 2500 की गयी।
- **खेलो इण्डिया योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपने सरकारी आवास पर 25 देशों की बाइक से यात्रा करने जा रही बाइकिंग क्वीन टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुये।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा जनहित में लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय

1. **पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला** लघु व सीमान्त किसानों का 01 लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ करने का निर्णय। इस योजना में लगभग 36 हजार करोड़ रुपये। 86 लाख से अधिक लघु व सीमान्त किसानों को लाभ मिला।
2. प्रदेश में संचालित अवैध पशु वधशालाओं को बन्द करने एवं यांत्रिक पशु वधशालाओं पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों को सख्ती से लागू करने का फैसला।
3. प्रत्येक जनपद में एण्टी रोमियो स्क्वायड के गठन और संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में क्षतिग्रस्त विद्युत ट्रांसफॉर्मर बदलने की नई व्यवस्था का प्रस्ताव मंजूर। किसानों के निजी नलकूप के क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर भी विभागीय वाहन से 48 घण्टे में बदलने की व्यवस्था।
5. बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत प्रदेश में 487 रु0 प्रति कुन्तल की दर से किसानों एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की व्यवस्था।
6. सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2013 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देते हुए वर्ष 2017 एवं 2018 की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 02 अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का निर्णय।
7. प्रदेश में इंसेफेलाइटिस एवं अन्य जल एवं विषाणुजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्णय।
8. गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित कराने एवं बकाया भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्णय।
9. प्रदेश के हर घर को सातों दिन, चौबीसों घण्टे विद्युत आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार के साथ 14 अप्रैल, 2017 को साइन किए जाने हेतु निर्धारित सहमति पत्र अनुमोदित किया गया।
10. बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल समस्या के समाधान की कार्य योजना को मंजूरी।
11. **14 अप्रैल, 2017 से ग्रामीण इलाकों को 18 घण्टे, तहसील व बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे एवं सभी जनपद मुख्यालयों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का फैसला।**
12. राज्य सरकार ने किसानों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी (निम्न व मध्यम) विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी।
13. घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप एवं लघु उद्योगों के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना को मंजूरी।
14. गोरखपुर सिविल टर्मिनल का नामकरण महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर तथा आगरा सिविल टर्मिनल का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर करने का निर्णय।
15. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2 वर्षों के लिए लागू करने का निर्णय।**
16. हर जिले में एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय।
17. सार्वजनिक अवकाशों को निर्बन्धित अवकाशों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर। महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसरों पर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में उनके

व्यक्तित्व, कृतित्व एवं प्रेरणाप्रद सीखों को वर्तमान युवा पीढ़ी में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से कम से कम एक घण्टे की सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का फैसला।

18. **शासकीय विभागों में ई–टेंडरिंग तथा ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली लागू करने का फैसला।**
19. **24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय।**
20. **नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन को मिलाकर नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के गठन का फैसला।**
21. **नगर पालिका परिषद अयोध्या एवं नगर पालिका परिषद फैजाबाद को मिलाकर नगर निगम अयोध्या बनाए जाने का प्रस्ताव मंजूर।**
22. **दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि 300 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रु० प्रतिमाह करने का फैसला।**
23. कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना हेतु नगर निगम गाजियाबाद की ग्राम अरथला स्थित भूमि को धर्मार्थ कार्य विभाग को निःशुल्क दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
24. जनता को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु चिकित्सकों की अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव मंजूर।
25. पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे परियोजना के आठों पैकेजों ई0पी0सी0 पद्धति पर अग्रेतर क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी।
26. पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मशती वर्ष मनाए जाने के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद की समिति की संस्तुतियां अनुमोदित।
27. **नगर पालिका परिषद मुगलसराय का नाम पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से 'दीनदयाल नगर' किए जाने का निर्णय।**
28. उ0प्र0 सचिवालय में पत्रावलियों के रख–रखाव के लिए ई–ऑफिस व्यवस्था लागू करने का निर्णय।
29. **उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना– 2014 यथा संशोधित– 2016 में भीड़ द्वारा कारित हिंसा/हत्या पीड़ित (माब लिंचिंग) को क्षतिपूर्ति एवं अन्तरिम राहत की धनराशि प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।**
30. **'समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना' का नाम परिवर्तित कर 'मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना' किया गया।**
31. प्रदेश के 68 जनपदों में **पं0 दीनदयाल**

उपाध्याय किसान समृद्धि योजना।

32. समूह 'ख' के सभी अराजपत्रित पद, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने का निर्णय।

33. बेसिक शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों व कुक–कम–हेल्पर का मानदेय बढ़ाकर 1500 रु0 प्रतिमाह किये जाने का फैसला।

34. मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में 01 अगस्त, 2017 से शिक्षा मित्रों को 11 माह तक 10 हजार रु0 मासिक मानदेय देने का निर्णय।

35. जनपद अमरोहा एवं हापुड़ के कार्तिक पूर्णिमा मेला गढ़मुक्तेश्वर, रामायण मेला–चित्रकूट, माँ ललिता देवी शक्तिपीठ अमावस्या मेला– नैमिषारण्य, माँ पाटेश्वरी शक्तिपीठ– देवीपाटन तुलसीपुर मेला, तथा माँ विन्ध्यवासिनी शक्तिपीठ मेला मीरजापुर के प्रान्तीयकरण का निर्णय।

36. पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट का एक अंश सीधे कामगारों को दिए जाने का निर्णय।

37. मुख्यमंत्री कृषक धन योजना, मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना तथा मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना लागू करने का फैसला।

38. वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र– छात्राओं को निःशुल्क जूता, मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराए जाने की नई योजना प्रारम्भ।

39. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना और संचालन के लिए लखनऊ में 500 सीटों के कॉल सेण्टर की स्थापना का निर्णय।

40. प्रयागराज मेला प्राधिकरण के गठन का निर्णय।

41. रामगढ़ ताल, गोरखपुर में प्रेक्षागृह एवं वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु रामगढ़ ताल के निकट स्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग की 05 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय।

42. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रावधानों को मंत्रिपरिषद की सैद्धान्तिक सहमति।

43. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए सुगमता से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) नियमावली–2009 में संशोधन।

44. उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन के गठन का निर्णय।

45. मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना' लागू करने का निर्णय।

46. **'एक जनपद एक उत्पाद योजना' के क्रियान्वयन का निर्णय।**
47. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना का निर्णय।
48. **मुख्यमंत्री आवास योजना–(ग्रामीण) लागू करने का निर्णय।**
49. **समस्त उचित दर की दुकानों में ई–पॉस मशीन स्थापित कर उनके माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने का निर्णय।**
50. **उ0प्र0 के मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय।**
51. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ आच्छादन में वृद्धि हेतु विभिन्न फसलों की उन्नतशील प्रमाणित एवं संकर प्रजातियों के बीजों पर राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
52. मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि 05 लाख रु0 से बढ़ाकर 10 लाख रु0 किए जाने को कार्योत्तर स्वीकृति।
53. आंगनबाड़ी केन्द्र पर 03 से 06 वर्ष के बच्चों को हॉट कुक्ड फूड योजना के माध्यम से गर्म खाना पकाकर खिलाने का निर्णय।
54. 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन' के संचालन का निर्णय।
55. **विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु प्रत्येक जनपद में एक एण्टी पावर थेफ्ट पुलिस थाना स्थापित करने का निर्णय।**
56. जनपद मथुरा में बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नन्दगांव, राधाकुण्ड तथा बल्देव मद्य निषेध क्षेत्र घोषित।
57. मगहर, जनपद संत कबीर नगर में कबीर दास अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित।
58. श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश–2018 लाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित।
59. पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु रोजगारपरक प्रशिक्षण योजना लागू करने का निर्णय ।
60. प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित पात्र लोगों को उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कराकर प्रभावी रूप से लागू कराए जाने का फैसला।
61. उ0प्र0 माटी कला बोर्ड के गठन का निर्णय।
62. लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को प्रतिमाह प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि को 15 हजार रु0 से बढ़ाकर 20 हजार रु0 किए जाने का निर्णय।
63. **नगर प्रतिकर भत्ते तथा मकान किराए भत्ते की 01 दिसम्बर, 2008**

से लागू दरों को 01 जुलाई, 2018 से दोगुना करने का निर्णय।

64. गन्ना किसानों का पेराई सत्र–2017–18 का बकाया गन्ना मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए चीनी मिलों द्वारा उक्त सत्र में की गई गन्ना खरीद के सापेक्ष 4.50 रु0 प्रति कुन्तल की दर से 500 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का निर्णय।

65. 'द उत्तर रियल स्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) (एग्रीमेन्ट फॉर सेल रूल्स) 2018' अनुमोदित।

66. जनपद, मण्डल एवं नगर निगम इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर जनपद 'प्रयागराज' किए जाने का निर्णय।

67. जनपद फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर जनपद अयोध्या एवं मण्डल फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर मण्डल अयोध्या किए जाने का निर्णय।

68. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना का निर्णय।

69. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव प्रदान करने का निर्णय। आंगनबाड़ी कार्यकत्री / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को 500 रु0 प्रतिमाह तथा आंगनबाड़ी सहायिका को 250 रु0 प्रतिमाह इन्सेन्टिव दिया जाएगा।

70. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू करने का फैसला।

71. सीवर / सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के सभी मामलों में मृतक के आश्रित परिवार को 10 लाख रु0 की तत्काल राहत प्रदान किए जाने का निर्णय।

72. डिफेन्स कॉरिडोर के लिए लैण्ड बैंक विकसित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।

73. पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत।

74. बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव अनुमोदित।

75. उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी।

76. भ्रष्टाचार निवारण व उन्मूलन के उद्देश्य से उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के 10 सेक्टर्स / इकाइयों को थाना घोषित किये जाने का निर्णय।

77. उ0प्र0 के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन की नीति अनुमोदित।

78. नदियों में मत्स्य आखेट हेतु पट्टा / ठेका का अधिकार दिए जाने के लिए नीति अनुमोदित।

79. **केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 12 जनवरी, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से 103वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को 14 जनवरी, 2019 से प्रदेश में प्रभावी किये जाने को सैद्धांतिक सहमति प्रदान गयी।**

80. **उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की 23 चीनी मिलों को पेराई 2019–20 के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि0/जिला सहकारी बैंकों द्वारा दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण अंकन 3221.63 करोड़ रु. (तीन हजार दो सौ इक्कीस करोड़ तिरसठ लाख मात्र रूपए) की शासकीय गारण्टी प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।**

81. आवास विहीन या कच्चे जर्जर आवासों में निवास कर रहे कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना–(ग्रामीण) की पात्रता में सम्मिलित किए जाने का निर्णय।

82. 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे' परियोजना के निर्माण के लिए 06 पैकेजों का ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु वित्त पोषण तथा निर्माणकर्ताओं के चयन के लिए प्रस्तुत **RFQ-cum-RFP** अभिलेख अनुमोदित।

83. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना के ई0पी0सी पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित वित्त पोषण तथा परियोजना के दोनों पैकजों के निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धी तैयार किये गये **RFQ-cum-RFP** बिड अभिलेखों का अनुमोदन।

84. एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के संकायी सदस्यों एवं गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एम्स के अनुरूप भत्ते अनुमन्य करने का निर्णय।

85. 'गंगा एक्सप्रेस–वे' के निर्माण को सैद्धान्तिक सहमति।

86. भरद्वाज ऋषि के आश्रम, श्रृंग्वेरपुर धाम प्रयागराज–चित्रकूट मार्ग पर पहाड़ी नामक स्थान पर स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के सौन्दर्यीकरण एवं विकास का निर्णय।

87. रबी विपणन वर्ष 2019–20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय नीति लागू करने का निर्णय। रबी खरीद वर्ष 2019–20 में प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य। प्रदेश में कुल 6,000 क्रय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। गेहूं क्रय की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 15 जून, 2019 तक प्रभावी रहेगी। गेहूं क्रय का मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे गेहूं क्रय के 72 घण्टे के अन्दर किया जाएगा।

88. महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों के अतिशीघ्र निस्तारण हेतु जनपद वाराणसी में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय।

89. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय।

90. कन्या सुमंगला योजना लागू करने का निर्णय।

91. लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहांपुर में वातानुकूलित मिनी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय।

92. अयोध्या में पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत पर्यटन आकर्षण की दृष्टि से भगवान श्रीराम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम, इण्टरप्रेटेशन सेण्टर, लाइब्रेरी, पार्किंग, फूड प्लाजा, लैण्डस्केपिंग एवं श्रीराम प्रतिमा एवं अन्य मूलभूत पर्यटक सुविधाओं के सृजन को मंजूरी।

93. वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही पेंशन राशि को 400 रु0 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 500 रु0 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी किये जाने का निर्णय।

94. 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' को मंजूरी।

95. 'उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति–2019' के प्रख्यापन को मंजूरी।

96. प्रथम बार बटाईदार व कॉन्ट्रैक्ट फारमर्स से भी धान खरीद। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 के लिए धान क्रय नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी।

97. 'उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति–2019' के प्रख्यापन को मंजूरी। प्रस्तावित नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी। यह नीति तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि इसके स्थान पर किसी नयी नीति का प्रख्यापन नही किया जाता है।

98. राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों का तृतीय सत्र (मंगलवार) दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को आहूत करने का प्रस्ताव अनुमोदित।

99. नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के मध्य पड़ने वाली सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि को नागरिक उड्डयन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय।

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल @myogiadityanath से कुछ चुनींदा ट्विट्स

पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किया गया एक पुनीत कार्य है और इस कार्य को एक जन अभियान बनाकर हम सबको करना चाहिए। आज दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित एनडीएमसी नर्सरी का भ्रमण किया और नर्सरी में आंवले के पौधे का रोपण भी किया।

2019–20 के शैक्षणिक सत्र में सरकारी कॉलेजों में मेडिकल सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जो चिकित्सा सेवा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सरकार ने देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की है। वर्तमान में उ.प्र. में 15 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं।

आज जम्मू–कश्मीर माँ भारती का अभिन्न अंग है। धन्यवाद मोदी सरकार देश को एक राष्ट्र, एक संविधान और एक ध्वज में पिरोने के लिए। 100 दिनों में ही सरकार के द्वारा कश्मीर को मुख्य धारा में लाने के लिए उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम का सभी भारतवासियों ने दिल से अभिनंदन किया है।

पोषण अभियान एक पवित्र अभियान है, जिसको बढ़ाने के लिए घर–घर तथा गांव–गांव यह अभियान पहुंचाना है, जिससे जन समुदाय में जागरूकता बढ़े। अंतर्विभागीय समन्वय, जन जागरूकता से ही हम सब कुपोषण की जंग जीत सकते हैं और उप्र में 'सुपोषण गूंज' की परिकल्पना साकार कर सकते हैं।

तीन तलाक बिल किसी मत,मजहब और जाति के लिए नहीं है बल्कि नारी गरिमा और उनके सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक था, मैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री / **narendramodi** जी का धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हम इस दिशा में अनवरत बढ़ते रहेंगे।

उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तभी भारत नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। उत्तर प्रदेश ने सुनिश्चित कर लिया है कि वो भारत के तीव्र आर्थिक विकास का इंजन बनेगा। हमने उत्तर प्रदेश को भय–मुक्त और व्यापार–युक्त बनाया है। आईये, हम सब मिल कर एक नया उत्तर प्रदेश बनाएं। **#GBC2**

हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है उ.प्र. में विकास की धारा को तीव्र गति देना जिससे हर एक नागरिक,हर एक वर्ग,शोषितों और वंचितों का सर्वांगीण विकास हो सके। GBC–2 में 65,000 Cr. के करीब 250 प्रोजेक्ट का शुभारंभ होगा। आइये,उत्तर प्रदेश में चल रही औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बनिये। #GBC2

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों की स्थापना में पहले स्थान पर है, इन उद्योगों की स्थापना से प्रदेश में न केवल आर्थिक समृद्धता को बल मिलेगा बल्कि रोजगार की भी व्यापक संभावनाएं बढ़ेंगी।

मुझे विश्वास है कि, यह बजट भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को साकार करने का रोडमैप देने के साथ ही 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में मजबूत कदम होगा।

भारत नहीं स्थान का वाचक,गुण विशेष नर का है एक देश का नहीं,शील यह भू–मण्डल भर का है जहाँ कहीं एकता अखंडित,जहाँ प्रेम का स्वर है देश–देश मे वहाँ खड़ा,भारत जीवित भास्वर है दिनकर जी का भारत ही नया भारत है आइये नए भारत के निर्माण में भागीदार बने

श्री /narendramodi जी का सपना 'सबका साथ–सबका विकास' है। #UP का चौकीदार बनने के बाद मैंने इसी दिशा में कार्य किया। चाहे गोरखपुर में जापानी बुखार का खात्मा हो, कुंभ का दिव्य व भव्य आयोजन, 24 घंटे बिजली, चुस्त कानून व्यवस्था या विकास की कोई भी परिकल्पना, हम हर कसौटी पर खरे उतरे हैं!

तुष्टिकरण के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी। प्रदेश के युवा तैयारी करें, नौकरी की कमी नहीं होने दी जाएगी। भाई–भतीजावाद अब नहीं चलेगा और नौकरी के नाम पर धांधली करने वाले लोग जेल भेजे जाएंगे और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

पिछली सरकारों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती थीं। बहुसंख्यक समाज के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। आज आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अपराधी या तो प्रदेश से पलायन कर चुके हैं या फिर राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल चुके हैं।

सूचना विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रकाशित प्रयागराज कुम्भ 2019 की कॉफी टेबिल बुक का विमोचन करते हुए

माननीय मुख्यमंत्री जी की विदेशी महानुभावों से भेंट

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपने आवास पर बेल्जियम के राजदूत श्री जॉन लूयक्स से शिष्टाचार भेंट करते हुये। 30 मई, 2017

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लोक भवन में एशियन डेवलपमेण्ट बैंक एवं राज्य सरकार के मध्य ऋण अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर। 27 जून, 2017

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शास्त्री भवन में जापान के राजदूत श्री केन्जी हिरामत्सू से भेंट करते हुये। 03 अक्टूबर, 2017

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यू0एस0 इण्डिया बिजनेस काउन्सिल की प्रेसीडेंट सुश्री निशा बिस्वाल ने लोकभवन में भेंट की। 30 नवम्बर, 2018

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर नीदरलैण्ड के प्रतिनिधिमण्डल से भेंट करते हुए। 14 नवम्बर, 2017

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सर्किट हाउस, वाराणसी में कनाडा से आए प्रतिनिधि मण्डल के साथ। 4 जनवरी, 2018, वाराणसी

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपने आवास पर बिल एण्ड मिलिन्डा गेट्स फाउनडेशन के सह अध्यक्ष श्री बिल गेट्स से मुलाकात के दौरान प्रतीक चिन्ह् भेंट करते हुए। 17 नवम्बर, 2017

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आवास पर नेपाल के पूर्व नरेश श्री ज्ञानेन्द्र बीर विक्रम शाह से भेंट करते हुए। 08 जनवरी, 2018

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में शास्त्री भवन में दक्षिण कोरिया के गिम्हे सिटी के मेयर श्री डू यून सू के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित करने के अवसर पर। 23 दिसम्बर, 2017

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनपद आगरा में इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू को 'कुम्भ–2019' का 'लोगो' भेंट करते हुये। 16 जनवरी, 2018

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शास्त्री भवन में भेंट करते मलेशिया के राजदूत दातो हिदायत अब्दुल हामिद। 01 फरवरी, 2018

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, जनपद वाराणसी में गंगा घाट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को नौकायन कराते हुये। साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। 12 मार्च, 2018

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 'उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट–2018' के दौरान थाईलैण्ड के प्रतिनिधिमण्डल से भेंट करते हुए। 22 फरवरी, 2018

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शास्त्री भवन में अमेरिका के राजदूत श्री केनेथ आई. जस्टर मुलाकात करते हुए। 06 जून, 2018, लखनऊ।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति तथा वर्तमान में मार्गदर्शक मंत्री, रक्षा मंत्री तथा रॉड्रिग्स के मंत्री सर अनिरूद्ध जगन्नाथ, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 'उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट–2018' के अवसर पर। 22 फरवरी, 2018

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,अपने सरकारी आवास पर इजराइल के राजदूत श्री डेनियल कैरमॉन से मुलाकात के दौरान प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए। 10 जुलाई, 2018

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शास्त्री भवन में वॉलमार्ट इण्टरनेशनल की सी.ई.ओ. सुश्री जूडिथ मैक्केना तथा फ्लिपकार्ट ग्रुप के सी.ई.ओ. श्री बिन्नी बंसल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल से भेंट करते हुए। 26 सितम्बर, 2018।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकभवन में यू0एस0 इण्डिया बिजनेस काउन्सिल की प्रेसीडेण्ट सुश्री निशा बिस्वाल ने भेंट की। 13 नवम्बर, 2018

देश ही नहीं, विदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी

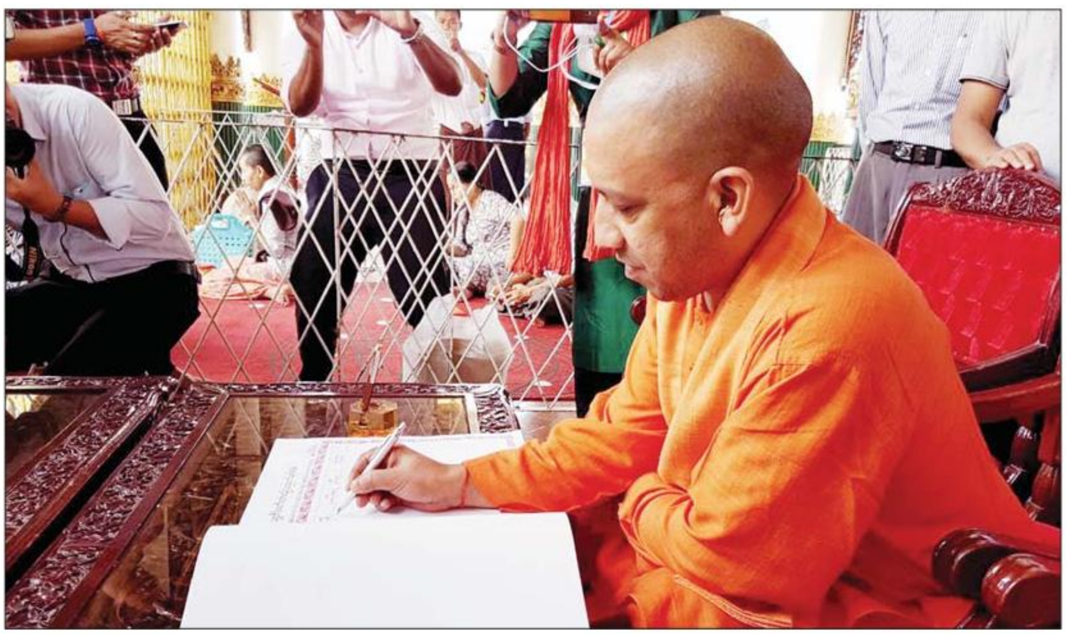

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, म्यांमार के श्वेडागॉन पगोडा में विजिटर्स बुक पर अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए। 06 अगस्त, 2017

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मॉरिशस स्थित रामायण सेण्टर के भ्रमण अवसर पर। 03 नवम्बर, 2017

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनकपुर, नेपाल में श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव के अवसर पर। 12 दिसम्बर, 2018

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रूस में भारत-रूस सहयोग के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रम में रूस के जबाइकल्सकी क्राई क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के मध्य कृषि और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के तहत एक एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किया गया।

12 अगस्त, 2019

भारत–रूस के ऐतिहासिक सम्बन्धों को नया आयाम देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 व 13 अगस्त, 2019 को रूस का भ्रमण किया। रूस के सुदूर पूर्व के जबाइकल्सकी क्राई क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं ऊर्जा विषय आधारित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में रूस और उत्तर प्रदेश के मध्य कृषि और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के तहत एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास की व्यापक सम्भावनाएं मौजूद हैं, जो हम सभी के लिए निवेश के अवसर प्रदान करती हैं।

सफलता की कहानी : लाभार्थियों की जुबानी

पहले की अपेक्षा मुसहर समाज को हर जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। राशन कार्ड, पेंशन, शौचालय, आवास व बिजली देकर प्रदेश सरकार ने मुसहर समाज का उत्थान किया है।

चंद्रिका मुसहर,
रामपुर गोनहा मुसहर, बस्ती

पति की नियमित आमदनी न होने के कारण सदा आर्थिक संकट रहता था। इस कारण से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते थे। ऐसे समय में ज़री-ज़रदोज़ी की मेरी कला काम आयी और ओडीओपी योजना के तहत ऋण की सुविधा मुझे प्रदेश सरकार द्वारा मिली। मैंने अपना वर्कशॉप शुरू किया है। अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंचना मेरा लक्ष्य है।

मधु
दरोगाबाद, उन्नाव

सरकार द्वारा संचालित की गई योजनाओं में आवास, शौचालय, पेंशन व बिजली का लाभ मिल चुका है। उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस का कनेक्शन लेने के लिए भी मैंने आवेदन किया है। सच मायनो में प्रदेश सरकार मुसहर समाज का भला कर रही है।

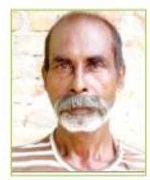

बन्हू मुसहर
रामपुर गोनहा मुसहर, बस्ती

उजाला हमारे नसीब में होगा, कभी इसकी कल्पना ही नहीं की थी। हम लोग बिजली के अभाव में मिट्टी के तेल से डिबिया जलाते थे। शाम होते ही पढ़ाई बंद हो जाती थी। सौभाग्य योजना ने हमारी तकदीर ही बदल दी। हमें बिजली का कनेक्शन मिल चुका है। अब हर जगह उजाला ही उजाला है। देर रात तक हम पढ़ते भी हैं। पहले रात में बाहर निकलने पर डर लगता था। अब कनेक्शन हो गया है तो अच्छा लगता है।

गोल्डी राज
ग्राम : किसनपुरी, जिला : खीरी

आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। सरकार की सौभाग्य योजना ने हमारे गांव को रोशन कर दिया। अब बिजली की रोशनी में उम्मीदों की नयी जिन्दगी प्रारंभ हुई है। अब गांव के बच्चे भी पढ़ने-लिखने लगे हैं।

इंद्रवती देवी ग्राम
भगवानपुर सुकरौली,
जिला कुशीनगर

अयोध्या दीपोत्सव का विश्व रिकार्ड

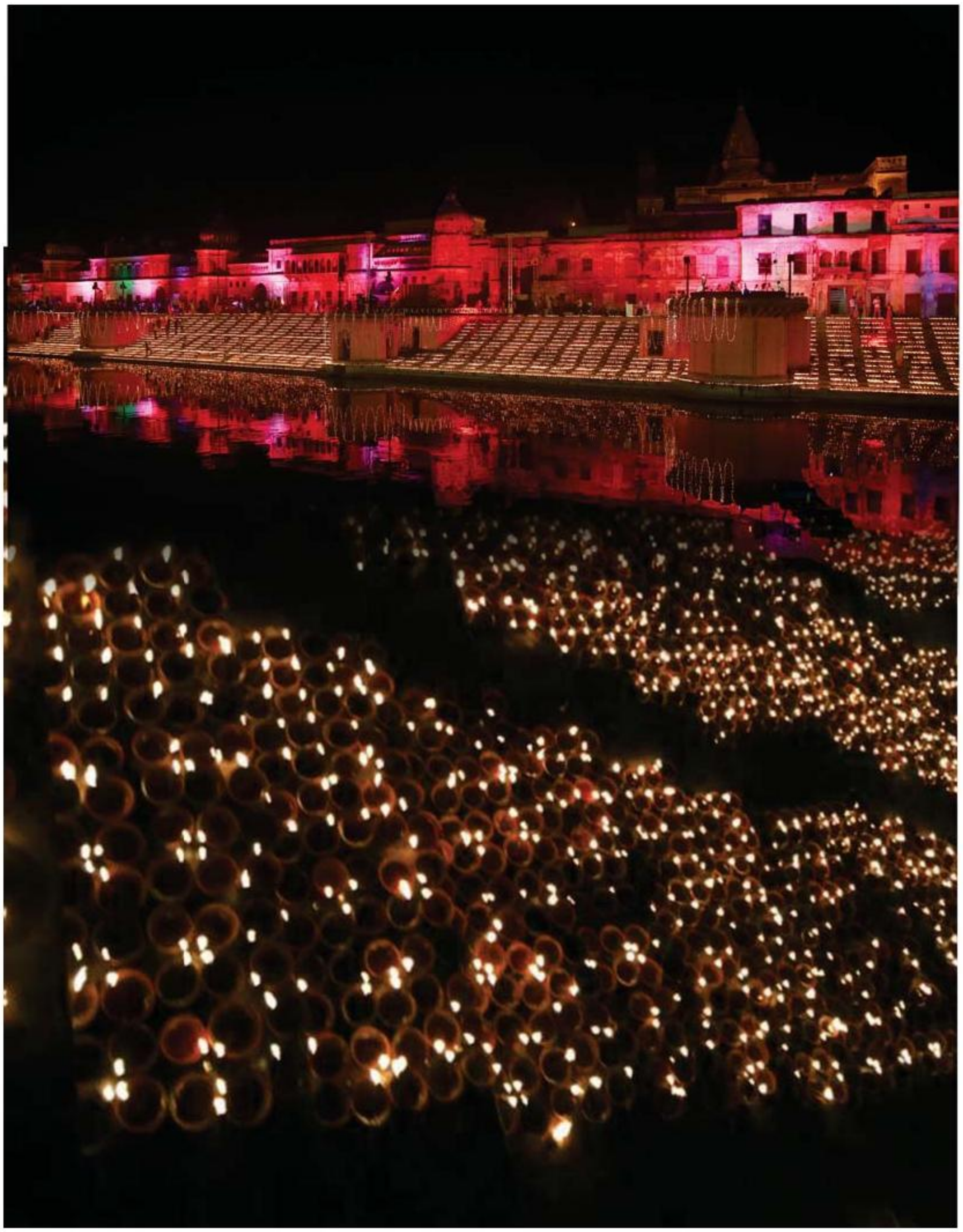

सौजन्य से- उत्तर प्रदेश सरकार

प्रमुख समाचार पत्रों की कलम से!

वाराणसी • बृहस्पतिवार, 22 फरवरी 2018 इन्वेस्टर्स समिट 2018

महानिवेश 4.48 लाख करोड़ की धनवर्षा

प्रदेश के बजट से ज्यादा निवेश

4.28 लाख करोड़ के एमओयू हुए, इतना ही बजट यूपी का भी

पीएम मोदी का तोहफा 20,000 करोड़ का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन निवेशकों ने दिल खोलकर किया एलान

42 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर

1045 एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

यूपी की तरक्की के लिए उद्योगपतियों ने खोला खजाना

यूपी में दिखने लगा है बड़ा बदलाव : मोदी

पीएम मोदी ने कहा- न्यू यूपी की नींव तैयार, अब लक्ष्य ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी

देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए महाराष्ट्र से प्रतिस्पर्धा का दिया लक्ष्य

4 पी से प्रदेश की प्रगति का मंत्र

देश को दुनिया में स्थापित करने का रास्ता यूपी से

यह समिट यूपी को बीमारू राज्य की छवि से उबारने की कड़ी

10 हजार करोड़ का निवेश

35 हजार करोड़ का निवेश

लखनऊ समेत छह जिलों को जोड़ेगा कॉरिडोर

आज भी 15 सत्रों में तय होगा निवेश का खाका

निवेशकों को निवेश-मित्र सिंगल विंडो की सौगात

वाराणसी में रिसॉर्ट, ऑटो फैक्ट्री, आईटी सेंटर और हेल्थकेयर

200 करोड़ का निवेश

आएगा ₹4.28 लाख करोड़ का निवेश

पीएम ने की यूपी इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत, 1045 एमओयू साइन हुए

अब रेड टेप नहीं रेड कारपेट मिलेगा : मोदी

मोदी के तीन मंत्र

गौतम अडाणी 35,000

कुमार मंगलम बिड़ला 25,000

सुभाष चंद्रा 18,700

मुकेश अंबानी 10,000

एन चन्द्रशेखरन

सौजन्य से- उत्तर प्रदेश सरकार

प्रमुख समाचार पत्रों की कलम से!

अमर उजाला

विकास की बुनियाद

निवेश परियोजनाओं का दूसरा शिलान्यास समारोह दिवाली तक

पिछली सरकारों में उद्योगों से टूट गए थे रिश्ते, अब मजबूत

डीजल-पेट्रोल का आयात खर्च कम करेंगी इलेक्ट्रिक बसें : योगी

नीयत साफ हो तो किसी के भी साथ खड़े होने से दाग नहीं लगता : मोदी

60,000

यूपी में औद्योगिक मानसून

- 60 हजार करोड़ का बरसा निवेश
- 81 परियोजनाएं धरातल पर
- उद्योगपतियों से रिश्ते रखने पर डर नहीं : मोदी
- 5 महीने में यूपी सरकार ने किया ऐतिहासिक काम

सहारा न्यूज ब्यूरो

लखनऊ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में पूंजी निवेश के जरिए रविवार को कांग्रेस व दूसरे विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा देश के विकास में उद्योगपतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए उद्योगपतियों से बेहतर रिश्ते और उनके साथ फोटो खिंचाने में मुझे कोई डर नहीं लगता।

प्रधानमंत्री ने राजधानी के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 60 हजार करोड़ रुपये निवेश की 81 उद्योगों की आधारशिला रखी और शिलान्यास ईंट पर अपने हस्ताक्षर भी किए। इसके बाद अपने सम्बोधन में कहा, 'सावन में निवेश की बारिश', यूपी ने पांच माह में इतना बड़ा पूंजी निवेश कराकर ऐतिहासिक और अकल्पनीय कार्य किया है। यूपी सरकार की यह उपलब्धि उसके प्रति बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक

पांच माह में 60 हजार करोड़ का निवेश अकल्पनीय

अटल ने देखा था समृद्ध भारत का सपना

प्रदेश में कार्य संस्कृति में बहुत कम समय में सकारात्मक बदलाव आया

60 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट आर्थिक और औद्योगिक असंतुलन दूर करेंगे

किस क्षेत्र में कितना निवेश

भारी उद्योग	26 फीसद
खाद्य प्रसंस्करण	17 फीसद
नवीकरणीय ऊर्जा	16.8 फीसद
इंफ्रास्ट्रक्चर	15.40 फीसद
ऊर्जा	14.73 फीसद
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स	11 फीसद
पर्यटन	10.10 फीसद
एमएसएमई	6 फीसद
पशुपालन	4 फीसद
आवास	8 फीसद
मेगा फूड पार्क	5 फीसद

लखनऊ। रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 60 हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, साथ हैं राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम द्वय केशव प्रसाद मौर्य, डा. दिनेश शर्मा व प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना।

जो काम एक साल में किया, सपा-बसपा सरकारें पांच वर्ष में नहीं कर सकीं : योगी

लखनऊ (एसएनबी)। यूपी में निवेश को धरातल पर उतारने के लिए आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के बाद पांच महीने के अल्प अंतराल में 60 हजार करोड़ के निवेश की 81 परियोजनाएं शुरू कराने में सरकार कामयाब रही और 50 हजार करोड़ की परियोजनाएं पाइप लाइन में हैं, उन्हें भी जल्द जमीन पर उतारा जाएगा। उनकी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और कोई भी कोना विकास से अछूता न रहे। (विवरण पेज 18)

50 हजार करोड़ की परियोजनाएं पाइप लाइन में

अगले कुछ माह में इन परियोजनाओं को भी उतारेंगे जमीन पर

नजरिए से उद्योगपतियों के जरिए कांग्रेस तथा अन्य दूसरे दलों के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, जिनकी नीयत साफ नहीं होती है वे डरते हैं और उद्योगपतियों से पर्दे के पीछे मिलते हैं। इसके विपरीत उन्हें (मोदी) उद्योगपतियों से सार्वजनिक तौर से मिलने में कोई गुरेज नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश का कोई उद्योगपति ऐसा नहीं होगा जिसने पिछली हुक्मरानों के दरबार में दंडवत न की हो। यहां बैठे अमर सिंह से बेहतर यह कौन जान सकता है।

महात्मा गांधी का जीवन इतना पवित्र था कि उन्हें बिरलाजी के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हुआ। वे उनके घर जाकर रुकते थे। उन्होंने कहा, मैं यूपी से ही सांसद हूं। ऐसे में यूपी की जनता का मुझ पर पूरा हक है। मैंने यूपी की 22 करोड़ जनता को कहा था कि उनके प्यार को ब्याज के साथ लौटाऊंगा। यह निवेश उसी कड़ी का हिस्सा है। डिजिटल इंडिया एवं मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। हम ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, जिसमें किसी के साथ भेदभाव न हो।

किसका कितना निवेश

रिलायंस ग्रुप	10 हजार करोड़ (यूपी)
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रा.लि.	10 हजार करोड़ (ग्रेटर नोएडा)
टेगना इलेक्ट्रानिक्स प्रा.लि.	5000 करोड़ (ग्रेटर नोएडा)
इंफोसिस लि.	5000 करोड़ (नोएडा)
बीएसएनएल	5000 करोड़ (यूपी)
पेटीएम	3500 करोड़ (गौतमबुद्ध नगर)
एस्सेल ग्रुप	3000 करोड़ (यूपी)
अडानी ट्रांसमिशन लि.	2600 करोड़ (घाटमपुर/हापुड़)
टाटा कंसल्टेंसी	2300 करोड़ (नोएडा)
लूलू ग्रुप इंटरनेशनल	2000 करोड़ (लखनऊ)

यह सभी निवेश 24 जिलों में हो रहा है। इसमें 53 फीसद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में, जबकि पूर्वांचल में 22 फीसद, मध्य यूपी और बुन्देलखंड में 27 फीसद निवेश होगा।

- निवेशकों को केन्द्र देगा अतिरिक्त सुरक्षा : राजनाथ -पेज 18
- खोयी लोकप्रियता बचाने में जुटे पीएम : अखिलेश -पेज 9

(संबंधित अन्य चित्र व खबरें पेज 2, 3, 18 और 19 पर)

- उत्तर प्रदेश में अगले तीन साल में 25 हजार करोड़ रुपये का करेंगे निवेश -कुमारमंगलम
- यूपी की योगी सरकार के गुड गवर्नेंस ने इंडस्ट्री को नया माहौल दिया - गौतम अडानी
- 1750 करोड़ रुपये के निवेश से देंगे 50 हजार रिक्शा -सुभाष चन्द्रा
- यूपी में 1000 करोड़ का निवेश करेगी आईटीसी -संजीव पुरी आईटीसी
- लखनऊ के बाद वाराणसी व नोएडा में खोलेंगे मेगामॉल -यूसुफ अली लूलू ग्रुप
- वाराणसी में लाएंगे आवास योजना -बीआर शेट्टी सीईओ एनएमसी ग्रुप

प्रमुख समाचार पत्रों की कलम से!

वाराणसी अमर उजाला 4

बृहस्पतिवार, 24 जनवरी 2019

प्रवासी भारतीय सम्मेलन

भारत के विकास में प्रवासियों के लिए असीम संभावनाएं हैं। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में हुई चर्चाओं और संवाद को निरंतरता प्रदान की जाएगी। प्रवासियों के अनुभव का लाभ लिया जाएगा।

- योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

दुनिया में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा भारत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- सम्मेलन की चर्चाओं और संवाद को दी जाएगी निरंतरता

विदेश मंत्री ने किया मेहमानों का स्वागत

ये प्रवासी किए गए सम्मानित

काशी महात्म्य के जरिए जड़ों से जुड़ेंगे प्रवासी

कई देशों की अगुआई की स्थिति में भारत

ब्लू इकोनॉमी, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा के क्षेत्र में होगा सहयोग

निवेश, नौकरियों का खुला पिटारा

65 हजार करोड़ की 292 परियोजनाओं का शिलान्यास, तीन लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

देश को आर्थिक महाशक्ति बनाएगा यूपी : योगी

कुंभ की स्वच्छता भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में

चौतरफा उजियारे के लिए 35922 करोड़

विश्व रिकॉर्ड बनाता प्रयागराज कुंभ

सौजन्य से- उत्तर प्रदेश सरकार

प्रमुख समाचार पत्रों की कलम से!

पर्यटन के विकास के लिए यूपी ने खोला खजाना

योगी सरकार ने प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। कुंभ का आयोजन इसका उदाहरण है। यह अब तक का सबसे अद्भुत आयोजन माना जा रहा है। श्रद्धालुओं की दृष्टि से भी कुंभ काफी सफल रहा। केंद्र के सहयोग से पर्यटन विकास की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। रामायण सर्किट, बौद्ध और ब्रज सर्किट में शामिल शहरों को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि यूपी घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में जल्दी ही देश में नंबर दो से नंबर एक पर आ सके। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के समुचित अवसर भी पैदा हो सकें। प्रदेश सरकार की मौजूदा नीतियों के कारण लाखों रोजगार सृजित होंगे।

'यूपी नहीं देखा तो इण्डिया नहीं देखा'

यूपी प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना

विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना एक अभिनव परियोजना है। इसके अंतर्गत प्रदेश के दो प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों-आगरा एवं ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन विकास संबंधी गतिविधियों के माध्यम से गरीबी-उन्मूलन और रोजगार-सृजन के लिए चिह्नित क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्मारकों व स्थलों पर मूलभूत पर्यटक सुविधाओं के सृजन एवं विकास के काम कराए जा रहे हैं। साथ ही उन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के आर्थिक/सामाजिक स्तर को सुधारने और रोजगार-परक अवसर के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित हैं।

इस परियोजना का लोन एग्रीमेंट एवं प्रोजेक्ट एग्रीमेंट विश्व बैंक एवं आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य 28 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना की कुल लागत 371.43 करोड़ रुपये है। इसमें विश्व बैंक 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत भार राज्य सरकार वहन करेगी।

योजना के अंतर्गत आगरा में शाहजहां पार्क एवं मेहताब बाग-कछपुरा का कार्य, वृंदावन में बांके बिहारीजी मंदिर क्षेत्र के पर्यटन विकास का कार्य जनवरी, 2018 में प्रारंभ करा दिया गया है। आगरा के कार्यों के लिए आगरा विकास प्राधिकरण और मथुरा जिले के कार्यों के लिए मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगायी कुम्भ में डुबकी

प्रयागराज कुम्भ 2019 में गंगा की आरती करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

483 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि से केन्द्र सरकार वित्त पोषित स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश में समेकित पर्यटन विकास के कार्य जारी

प्रासाद योजना में स्वीकृत कार्य

9.36 करोड़ रुपये से मथुरा-वृंदावन में टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का निर्माण

14.93 करोड़ रुपये से मथुरा-वृंदावन मेगा टूरिस्ट सर्किट (फेज-2) का कार्य-थीम पार्क अकबरपुर मथुरा का पर्यटन विकास, जयकुंड जैत का पर्यटन विकास, चंद्र सरोवर चौमुंहा का पर्यटन विकास, कृष्ण सरोवर बाद का पर्यटन विकास

7.34 करोड़ रुपये से जनपद-वाराणसी के सारनाथ में ध्वनि एवं प्रकाश-शो का कार्य

10.72 करोड़ रुपये से वाराणसी में अस्सी घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन

पर्यटन विकास की प्रमुख योजनाएं

- स्वदेश दर्शन योजना में हेरिटेज सर्किट एवं स्प्रिचुअल सर्किट-1 एवं 2 के लिए रु. 138.95 करोड़ की स्वीकृति।
- वाराणसी में पर्यटन विकास हेतु रु. 441.64 करोड़ के कार्य जारी।
- घरेलू पर्यटन स्थलों के विकास हेतु रु. 372 करोड़ का परिव्यय।
- कुम्भ क्षेत्र में 'संस्कृति ग्राम' की स्थापना।

ब्रज क्षेत्र में समेकित पर्यटन विकास

मथुरा। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अंतर्गत पर्यटन विभाग की ओर से मथुरा एवं वृंदावन में समेकित पर्यटन विकास के लिए 81.65 करोड़ रु. की लागत से विकास कार्य कराये जा रहे हैं। इनमें से प्रमुख हैं-

- वृंदावन परिक्रमा मार्ग के विकास के लिए बिजली और सिविल कार्य।
- गोवर्धन में बड़ी एवं छोटी परिक्रमा मार्ग बाउंड्रीवाल का निर्माण और विकास कार्य।
- गोवर्धन में स्थित भरना खुर्द सूर्यकुंड का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण।
- गोवर्धन बस स्टैंड के सामने कंट्रोल रूम, मीटिंग हॉल और वीआईपी गेस्ट हाउस का निर्माण। बरसाना में गोवर्धन के पास यात्री जन सुविधा केंद्र तथा विश्राम स्थल का निर्माण।
- बरसाना में राधारानी मंदिर के पास यात्रियों के लिए जलपान गृह का निर्माण और संपर्क मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था।
- नंदगांव में रंगीली चौक के नंद बाबा मंदिर और वीआईपी पार्किंग से नंद बाबा मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियों का पुनर्निर्माण कार्य एवं पार्किंग व जनसुविधा केंद्र का निर्माण।
- गोकुल स्थित रसखान समाधि में इंटरप्रेटेशन सेंटर का पुनर्विकास व जनसुविधा केंद्र का निर्माण।
- गोकुल स्थित नंद भवन परिसर में पार्किंग से मंदिर तक पहुंच मार्ग का पुनर्विकास एवं सुंदरीकरण का कार्य।
- मथुरा जिला में गोवर्धन स्थित बस स्टैंड का पुनर्विकास।
- मथुरा में गोवर्धन में सहकारी समिति के भवन तथा क्रय-विक्रय केंद्र का निर्माण कार्य।
- मथुरा स्थित जुबली पार्क में मल्टीलेवल भूमिगत पार्किंग स्ट्रीट वेंडर्स के स्थान और ओपन एम्फीथियेटर के निर्माण कार्य।

346.92 करोड़ रुपये के कार्य हो रहे मथुरा-वृंदावन में

प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त, 2018 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को ब्रज-विकास उत्सव के रूप में मनाया। इस मौके पर मथुरा-वृंदावन में 346.92 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

मंडलों में कराये जा रहे कार्य

लखनऊ। पर्यटन विकास के लिए विभिन्न मंडलों में हो रहे कार्य

गोरखपुर मंडल में समेकित पर्यटन विकास के लिए 183.87 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम हो रहा है।

अयोध्या में समेकित पर्यटन विकास के 142.74 करोड़ रुपये के कार्य चालू हैं।

वाराणसी मंडल में समेकित पर्यटन विकास के लिए 441.64 करोड़ रुपये के काम कराए जा रहे हैं।

मथुरा-वृंदावन में समेकित पर्यटन विकास के लिए 46.46 करोड़ रुपये के कामों पर काम हो रहा है।

आगरा मंडल में समेकित पर्यटन विकास के लिए 205.21करोड़ रु.की परियोजनाओं पर काम तेजी से हो रहा है।

प्रयागराज मंडल में समेकित पर्यटन विकास के लिए 66.29 करोड़ रुपये के कार्य चल रहे हैं।

लखनऊ मंडल में समेकित पर्यटन विकास के लिए 151.05 करोड़ रुपये के कार्य क्रियान्वयन के अलग-अलग चरण में हैं।

झांसी मंडल में समेकित पर्यटन विकास के लिए 56.09 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं।

मेरठ मंडल में समेकित पर्यटन विकास के लिए 52.63 करोड़ रुपये के कार्य जारी हैं।

बरेली मंडल में समेकित पर्यटन विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपये के कार्य चल रहे हैं।

सौजन्य से- उत्तर प्रदेश सरकार

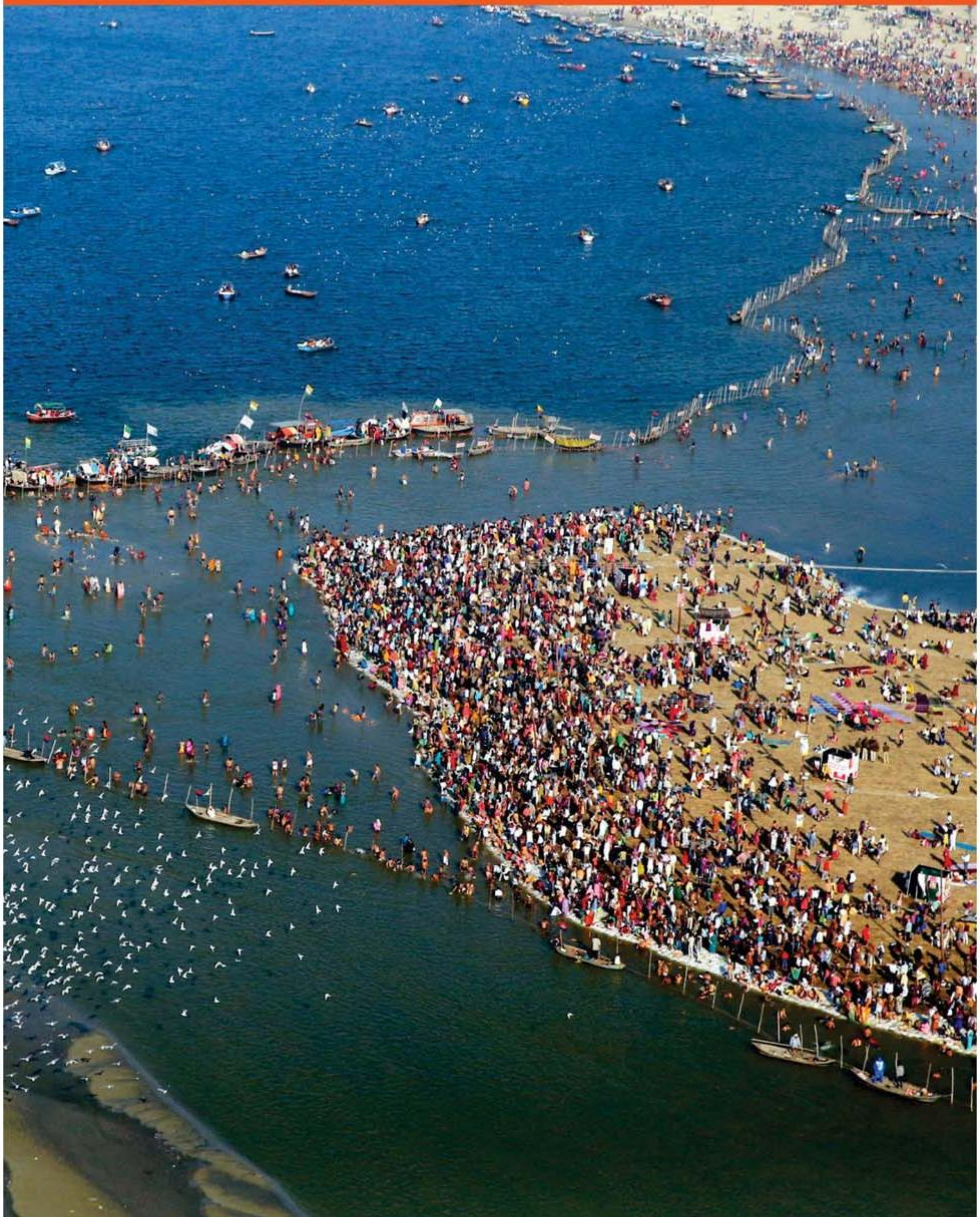

सौजन्य से- उत्तर प्रदेश सरकार

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

"प्रयागराज में 'दिव्य कुंभ एवं भव्य कुंभ' तथा वाराणसी में 'प्रवासी भारतीय दिवस' का एक ही समय में आयोजन कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व के समक्ष अपनी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया है। इन आयोजनों के लिए योगी जी एवं उनके प्रशासन को दिल से बधाई देता हूँ।"

– नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश